



**इण्डियन ओवरसीज बैंक**  
**Indian Overseas Bank**  
 आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with



## 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम

(रूपये लाख में)

**विजनेस मिक्स**  
 ₹ 5,28,773 Cr. ↑

**सकल अग्रिम**  
 ₹ 2,30,092 Cr. ↑

**परिचालन लाभ**  
 ₹1,676 Cr. ↑

**निवल लाभ**  
 ₹633 Cr. ↑

**सकल एनपीए**  
 ₹6,649 Cr. (2.89%) ↓

**निवल एनपीए**  
 ₹1,154 Cr. (0.51%) ↓

**पीसीआर**  
 96.96% ↑

**सीआरएआर**  
 17.82% ↑

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		30.06.2024 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	7,56,800	6,22,734	29,70,599	7,58,747	6,23,415	29,73,097
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और/या असाधारण मद से पहले)	73,799	50,736	3,41,253	75,384	51,109	3,42,274
3	कर से पहले की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	73,799	50,736	3,41,253	75,384	51,109	3,42,274
4	कर के बाद की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	63,281	50,035	2,65,561	64,866	50,403	2,66,566
5	अवधि के लिए कुल समेकित आय (कर के बाद) अवधि के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) और अन्य समेकित आय (कर के बाद)	लागू नहीं					
6	प्रदत्त इन्विटी शेयर पूंजी	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़ कर)			6,31,725			5,93,064
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790
9	मालियत	17,82,403	15,13,295	18,06,918			
10	प्रदत्त ऋण पूंजी/ बकाया ऋण (%)						
11	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर						लागू नहीं
12	ऋण इन्विटी अनुपात	1.96	1.32	1.46			
13	प्रति शेयर लाभ (प्रत्येक रु. 10/- पर) (सतत एवं असतत परिचालन हेतु)						
	1. मूल :	0.33	0.26	1.40			लागू नहीं
	2. घटाया गया	0.33	0.26	1.40			
14	पूंजी मोचन आरक्षितियाँ						लागू नहीं
15	डिबेंचर मोचन आरक्षितियाँ						लागू नहीं
16	कर्ज-शुल्की कवरेज अनुपात						लागू नहीं
17	ब्याज सर्विस कवरेज अनुपात						लागू नहीं

**टिप्पणी:**

- उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 एवं 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (बीएसई: www.bseindia.com एवं एनएसई: www.nseindia.com) एवं बैंक की वेबसाइट www.ioib.in पर उपलब्ध है।
- कुल समग्र आय और अन्य समग्र आय के संबंध में सूचनाएँ नहीं प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि इंड - एएस बैंक पर अब तक लागू नहीं किया गया है।
- सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 52(4) में संदर्भित अन्य मदों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) को संबंधित प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं, जिन्हें दिए गए यूआरएल पर देखा जा सकता है। (बीएसई: www.bseindia.com और एनएसई: www.nseindia.com)

दिनांक : 22.07.2024  
 स्थान : चेन्नै

धनराज टी  
 कार्यपालक निदेशक

जयवीर बत्ता राय  
 कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव  
 एमडी व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर  
 गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

# आइओबी के साथ बैंकिंग अनुभव बढ़ाएं



**आपकी सभी बैंकिंग  
 जरूरतों के लिए  
 ऑल-इन-वन  
 समाधान**

**digital.ioib.in**

**डिजिटल  
 बचत  
 खाता**

**डिजिटल  
 पेंशनर जीवन  
 प्रमाण पत्र**

**ऑनलाइन  
 लॉकर  
 आवंटन**

**डिजिटल  
 रीटेल  
 ऋण**

**डिजिटल कृषि  
 ऋण**

**क्रेडिट  
 कार्ड**

**डिजिटल  
 पीएमजेजेबीवाई  
 पीएमएसबीवाई**

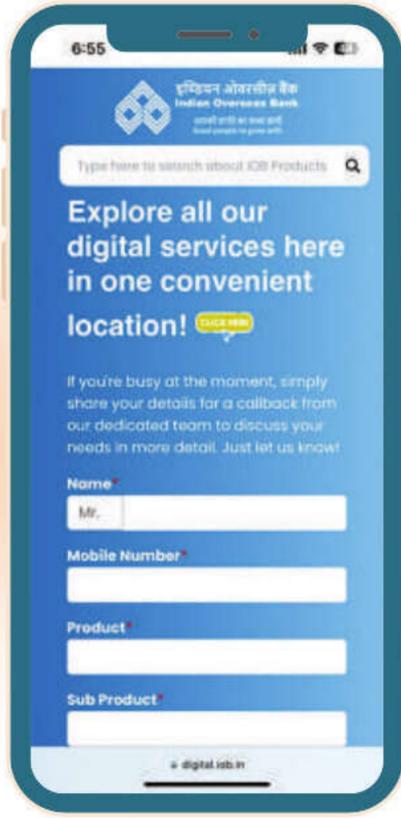
**ई-खाता  
 विवरण**

**ब्याज  
 प्रमाण-पत्र**

**बिना दावे  
 वाली जमाओं  
 को खोजें**

**डिजिटल  
 एसएचजी  
 ऋण**

**डिजिटल  
 केसीसी  
 ऋण**



साइबर धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के **1930** डायल करें

हमें फॉलो करें  
 @IOBIndia

1800 890 4445  
 1800 425 4445  
 www.ioib.in  
 digital.ioib.in

सिर्फ एक मिस्ट कॉल  
**+91 9210622122**  
 चट और पाएं अपने खाते के बैलेंस की जानकारी एएसएमएस के माध्यम से



कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

## नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा, भोजनालय के मालिकों के नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा जरूर दें।



जवाब देने को कहा।

मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया था। पीठ ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही कहा कि भोजनालयों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक किया जा सकता है कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे

पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। **शीर्ष अदालत** ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा व अन्य की कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

शाकाहारी हैं या मांसाहारी। पीठ ने इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है कि उसके पास कौन से खाद्य पदार्थ हैं लेकिन उन्हें मालिकों, कर्मचारियों के

नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल और गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन आफ प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स' की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक आदेश पारित किया गया है। सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है और यह संविधान के खिलाफ है। 'एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स' **बाकी पेज 8 पर**

लोकसभा में प्रधान व विपक्षी नेताओं में तीखी बहस

## लोकसभा में प्रधान व विपक्षी नेताओं में तीखी बहस

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा ( नीट ) को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन कर अपना विरोध दर्ज कराया।



लोकसभा में आमने-सामने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

नीट यूजी में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत नहीं : सरकार

प्रधानमंत्री का गला घोटने, आवाज दबाने का प्रयास हुआ : मोदी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने डार्डि घंटे तक देश के 'प्रधानमंत्री का गला घोटने' और आवाज दबाने का प्रयास किया।

राहुल गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत खामियां हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने आपको छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहराया है।' उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस मामले में व्यवस्थागत स्तर पर **बाकी पेज 8 पर**

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आइआइटी दिल्ली की टीम प्रश्न के सही उत्तर पर रपट सौंपे **पेज 8**

## सरकारी कर्मियों पर से रोक हटाने की हमने नहीं की थी मांग : आरएसएस

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का सोमवार को स्वागत किया।

प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा।

## सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के दोनों सदन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जहां एक प्रश्न के माध्यम से यह **बाकी पेज 8 पर**

मुद्दा उठाया गया, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठाई। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी। लोकसभा में जनता दल (एकी) के सदस्य रामप्रत मंडल ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार **बाकी पेज 8 पर**

## निपाह : जान गंवाने वाले लड़के के संपर्क में आए 406 लोगों में संक्रमण का खतरा

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दुर्लभ संक्रमण से जान गंवाने वाले 14 वर्षीय लड़के के संपर्क में आने के कारण निपाह वायरस से संक्रमित होने के खतरे का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 406 हो गई है, जिनमें से 194 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जाज ने सोमवार को यह जानकारी दी।

**केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 194 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं।**

केरल का स्वास्थ्य विभाग 13 लोगों के परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है, जिनके नमूने परीक्षण के लिए कोझिकोड मेडिकल कालेज की विभागीय विज्ञान प्रयोगशाला और तिरुवनंतपुरम के 'एडवॉर्ड वायरोलोजी इंस्टीट्यूट' में भेजे गए थे।

उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में से छह व्यक्तियों में लक्षण दिखे हैं जिनमें से तीन लोग द्वितीयक संपर्क सूची के हैं। भले ही मृत लड़के के माता-पिता में लक्षण नहीं हैं फिर भी हमने सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उनके नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संपर्क में आए लोगों की सूची में दो व्यक्ति पलक्कड़ के हैं, जबकि चार तिरुवनंतपुरम के हैं। पलक्कड़ के दो लोग एक निजी अस्पताल में फिहलाल काम कर रहे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम के चार लोग इलाज के लिए पेरिथलमना पहुंचे हैं।

## बजट आज, संसद में आर्थिक समीक्षा पेश संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का अनुमान

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए परिदृश्य उज्वल है, लेकिन उसे 'झटकों' के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनके दल ने लिखा है।

संसद में मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले पेश सरकार की आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का सतर्क अनुमान जताया गया है। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन से अधिक प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) का समर्थन किया गया है।

समीक्षा में खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर गौर करने का भी सुझाव दिया गया है। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। इसमें बढ़ते शेयर बाजार को लेकर भी आगाह किया गया है। कहा गया है कि खुदरा निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है और अति आत्मविश्वास **बाकी पेज 8 पर**

हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत पर जोर



संसद में सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

### 'महंगाई पर गौर करना बंद करे आरबीआइ'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रिजर्व बैंक को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि गरीबों को 'कूपन' दे या सीधे नकदी। **पूरी खबर पेज 10**

सात फीसद वृद्धि दर का अनुमान मानसून पर निर्भर : मुख्य आर्थिक सलाहकार **पेज 10**

## बहस पूजा खेडकर और यूपीएससी में दिव्यांग कोटे का मामला

## सवाल उठाकर विवादों में घिरीं वरिष्ठ अधिकारी

जानसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिव्यांग मानदंडों के तहत परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी पूजा खेडकर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच तेलंगाना की वरिष्ठ अधिकारी सिमता सभरवाल ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआइएस) में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने आइएएस अधिकारी की टिप्पणियों को तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को 'संकीर्ण दृष्टिकोण' से नहीं देखा जाना चाहिए,

**अधिकारी** ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (आइएएस, आइपीएस, आइएफओएस) की प्रकृति लंबे समय तक क्षेत्र में कार्य कर लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है? इस पोस्ट पर शिवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बहिष्कारवादी दृष्टिकोण **बाकी पेज 8 पर**

सभरवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कि क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (आइएएस, आइपीएस, आइएफओएस) की प्रकृति लंबे समय तक क्षेत्र में कार्य कर लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है? इस पोस्ट पर शिवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बहिष्कारवादी दृष्टिकोण **बाकी पेज 8 पर**

एश्योरन्स ऑफ दि लीडर

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लि.

मना रहा है

# स्थापना दिवस

23 जुलाई 2024 को

# 106 वां

वर्ष देश सेवा को समर्पित

1919 - 2024

"हम पर भरोसा करने के लिए भारत देश का धन्यवाद"

हमारे प्रमुख उत्पाद

- स्वास्थ्य बीमा
- मोटर बीमा
- परियोजना और भिजली बीमा
- अग्नि बीमा
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- विमानन बीमा

+91 98333 19191

www.newindia.co.in @newindassurance

24x7 - टोल फ्री नंबर 1800-209-1415

प्रधान कार्यालय: न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, भारत

IRDAI REGN No. 190 CIN: L68000MH1919G0000526 Advt No.: NIA/24-25/191(H)

# जनसत्ता

## क्लासीफाइड

### व्यक्तिगत

**I,hitherto** known as ROHAN KUMAR alias ROHAN SINGH,S/O- SHAMSHER SINGH,R/O-Anwal(125),Rohtak Haryana-124411,have changed my name and shall hereafter be known as ROHAN SINGH. 0040739640-8

**I,hitherto** known as AJAY MISHRA alias ANIKET MISHRA,S/O,KAPILDEV MISHRA,R/O,Gram-Dhamur Gopal,Post- Pipra Chardrabhan,Deoria,Deoria,Uttar-Pradesh- 274001,have changed my name and shall hereafter be known as ANIKET MISHRA. 0040739638-3

**I,SHIV KISHOR DIXIT,S/O-RAM SHANKAR DIXIT,R/O-B-14/207,Eco-Village-2,Plot.No-GH01, Sector-16B,Greater-Noida West, Noida, P.O:Noida,DI:STT:Gautam Buddha,Nagar,uttar pradesh-201301, declare that name of my daughter has been wrongly written as AARJU in The actual name of my daughter is AARJU DIXIT. 0040739640-9**

**I,SAYEED AHMAD,S/O Shri Nazeer Ahmad,R/O E-176 Shahed-Nagar,Sahibabad Chikamberpur Ghaziabad,U.P,declare that my name and Date-of-Birth has been wrongly written as Sayeed Ahmed & 07.02.1960 in my passport no-K5512397 documents.The actual my name is SAYEED AHMAD, S/o-Nazeer Ahmad & date-of Birth-03.05.1960,For all the future purposes. 0040739592-8**

**I,Rizwan Ahmed,R/O A-48,Vivek Vihar,Phase-2,New Delhi-110095,have changed the name of my minor son from Mohammed Hamza to Mohd Hamza. 0040739648-4**

**I, Rukhsana Begum, W/o Mohd Zia, R/O I-21, Thokar No.4, Abul Fazel Enclave Part-1, Jamia Nagar,Okhla, New Delhi-110025, have changed my name to Rukhsar. 0040739604-10**

**I,Ritika Aggarwal W/o Ankur Sharma,R/O 183,Sector-17,Faridabad have changed my name to Ritika Aggarwal Sharma after marriage. 0040739592-4**

**I,Rajiv Mehta,S/O-Satya Pal R/O-Flat.No.18,Geeta-Apartment,Geeta-Colony,Delhi-110031,have changed my name to Rajeev Mehta,Rajiv Mehta and Rajeev Mehta is one and the same person. 0040739604-3**

**I,RAHUL CHAUHAN,S/O-VIJAY SWAROOP,R/O-Mohalla Fauladpura Malkhan Singh Chowk, Deoband, Saharanpur,Uttar Pradesh-247554,declare that name of mine, my father has been wrongly written as RAHUL SHARMA and VIJAY SHARMA in my-10th and 12th-Class educational documents.The actual name of mine, my father are RAHUL CHAUHAN and VIJAY SWAROOP. 0040739638-4**

**I, DHARAM VIR SINGH, R/O. WZ-501, NARAINA VILLAGE, N.D-28 CHANGED MY NAME TO DHARAM VEER SINGH. 0130043655-1**

**I,Karam Chander Aggarwal, S/O-Jagdish Prasad Aggarwal,R/O-3129/227, G.F., Chander Nagar,Trinagar, Delhi-110035,have changed my name to Karam Chand Aggarwal 0040739640-4**

**I,Krishan Singh,S/O Trilok Singh, R/O H.No.C-4/319, Yahuma Vihar, Delhi-110053,declare that name of my wife has been wrongly written as KAMLA DEVI in my service record.The actual name of my wife is KAMLA BISHT, which may be amended accordingly. 0040739570-1**

**I,Krishnanand S/O Chhatra Dhari R/O- RZV-54, Nihal Vihar, Gali No-5,Nangloi, Delhi-110041,Have change my name to Krishna Nand 0040739635-7**

**I,MOHD NAZIM,S/O Nasir Ahmad,R/O A-389,near-Jama masjid j j colony Old-Seemapuri Delhi-95,Declare that name of my has been wrongly written as Mohammed Nazim,S/o-Naseer Ahmad in my passport-no-16687695 documents.The actual my name is Mohd Nazim,for all the future purposes. 0040739592-9**

**I,MEENA,W/O GURVINDER BABLA,R/O B-800,SAINIK COLONY SECTOR-49, FARID-ABAD HARYANA-121001, have changed my name to MEENA BABLA, for all future purposes. 0040739595-3**

**I,MUDIT SHARMA,S/O ANIMESH SHARMA,R/O-C-3/301,EAST-ERN HEIGHTS,NYAY-KHAND-3 INDIRAPURAM,GHAZIABAD U.P-201014 HAVE CHANGED MY NAME TO ADVIK SHARMA,FOR ALL FUTURE PURPOSES. 0040739648-3**

**I,Partik,S/O Neranjan Vig R/O H.No-5516,Jain Mandir Mohalla, Jain Puri, Rewari (Haryana)-123401, have changed my name to Parteeek. 0040739604-4**

**I,Mohd Shuaib,S/O Late Sharif Ahmad,R/O-1209,Gali No.-39/4, Jafraabad,Delhi-110053,have changed my name from Mohd Shuaib to Mohammad Shuaib,for all future purposes. 0040739604-1**

**I,PRAMOD KUMAR S/O Kishan Singh, R/O B-47 Gali No.2,Nakul Marg,North, Chhajipur Shahdara Gokal Pur Delhi-110094 declare that name of my minor son has been wrongly written as LOVE SAINI in my minor son namely LOVE aged 15 years in his school record.The actual name of my minor son is LOVE. 0040739635-9**

**I,PARDEEP, S/O. MR.CHAND SINGH,R/O- RZF-905/21A, 2ND FLOOR,LBS MARG,RAJ NAGAR-II,PALAM COLONY,NEW DELHI-110077,inform that PARDEEP & PARDEEP LOHCHAB,both names are same person. 0040739604-7**

**I,NARENDER SINGH CHAUHAN,S/O-KHYURAJ SINGH CHAUHAN,R/O-A-37,Vasant-Marg, Vasant-Vihar,South-West Delhi-110057,declare that name of my father has been wrongly written as K H YUVRAJ SINGH CHAUHAN in my 10th-Class Educational Documents and Graduation-Degree(BCA).The actual name of my father is KHYURAJ SINGH CHAUHAN. 0040739592-10**

**I,Amandeep Singh Jaggi S/O Bhupinder Singh Jaggi R/O 2-C/40, 1ST-Floor,New Rohtak Road,Karol Bagh, W.E.A,Delhi-110005,that my children school records Jaskaran Singh and Darsh Deep Kaur my name is wrongly written/mentioned as Amandeep Singh instead of Amandeep Singh Jaggi. Which may be amended accordingly. 0040739640-5**

**I,NAHEEM,S/O-Allanoor R/O,Village Sirsa Kalan Ahtmali,Tehsil,Hasanpur,Police-Station, Rehra,Post Rehra,Block,Gangeshwari,Dist rict-Amroha(Uttar Pradesh)-244255,have changed my name to Mohd Naeem for all purposes. 0040739592-7**

**I,NADEEM AHMAD,S/O-NAEEM AHMAD,R/O-47,NAI-BASTI OKHLA,NEW-DELHI 110025,IN MY PASSPORT MY AND MY FATHER NAME ARE INCORRECT-NADEEM AHMED,S/O-NAEEM AHMED CORRECT NAME ARE NADEEM AHMAD,S/O-NAEEM AHMAD. 0040739600-5**

**I,Manisha Goel alias Manisha Jindal,D/o Surendra Kumar Goyal W/o Manish Jindal,R/O H-112,Phase-1,Ashek Vihar Delhi-110052,have changed my name to Manisha Jindal. 0040739635-8**

**I,GURVINDER LAL,S/O-TIRATH BABLA,R/O-B-800,SAINIK COLONY, SECTOR-49, FARID-ABAD,HARYANA-121001,changed my minor son name AYAN to AYAN BABLA,For all,future purposes 0040739595-5**

**I,SHAKUNTALA DEVI W/O Prateek Singh R/O Mansoorpur, Semra Larpur,Rampur, UP-244924,have changed my name to Shakuntla Devi for all purposes. 0040739642-1**

**I,SHARANYAA W/O Santhanagopalan,K R/O, Flat-No.135, Sahyog-Apartments, Mayur-Vihar Phase-1, Delhi-110091 have changed my name to Sharanyaa.S for all purposes. 0040739642-1**

**I,Shakuntala Devi W/o Prateek Singh R/O Mansoorpur, Semra Larpur,Rampur, UP-244924,have changed my name to Shakuntla Devi for all purposes. 0040739575-1**

**I, Satish S/O Tara Chand R/O FCA 43,Bhimsen Colony,Ballabgarh, Faridabad have changed my name to Satish Sharma. 0040739592-1**

**I, Sandeep Kumar Aggarwal (alias Sandeep Aggarwal) s/o Jyotinder Pal r/o A-1/46, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to SANDEEP KUMAR. 0040739616-1**

**I, HIMANSHU S/O-ANIL KUMAR CHOPRA,R/O-PLOT.NO-117, NEAR-GURDWARA, CHAND-NAGAR,WEST DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO HIMANSHU CHOPRA,FOR ALL PURPOSES 0040739600-10**

**I, Sourabh Mehra S/o Mahesh Chander Mehra residence F-39/766A, Gali No-10, Ganesh Nagar-2, Shakarpur, East Delhi-110092 have changed my name from SOURABH MEHRA to SOURABH MEHRA for all future purposes. 0040739609-9**

**I,HIMANSHU SAKHUJA S/O LALIT SAKHUJA R/O 46/8, FIRST-FLOOR EAST PATEL NAGAR KALINDI COLLEGE CENTRAL DELHI-110008, HAVE CHANGED MY NAME TO HIMANSHU SAKHUJA. 0040739635-6**

**I,ANIL KUMAR,S/O-KUNDAN LAL CHOPRA,R/O-PLOT NO-117,NEAR-GURDWARA, CHAND-NAGAR,WEST DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO ANIL KUMAR CHOPRA FOR ALL PURPOSES. 0040739600-9**

**I,Hazi Yameen,S/O Mohd Yunus,R/O H.No.A-1383, A-Block, Gali.No-23,Shri Ram-Colony, Rajiv-Nagar,Delhi-110094,have changed my name to MOHD YAMIN. Permanently. 0040739595-9**

**I,GURVINDER LAL,S/O TIRATH BABLA,R/O-B-800 SAINIK COLONY SECTOR-49,FARID-ABAD HARYANA-121001,changed my minor Daughter name BHOOMI to BHOOMI BABLA,For,all,future purposes. 0040739595-6**

**I,ANIL KUMAR,S/O-KUNDAN LAL CHOPRA,R/O-PLOT NO-117,NEAR-GURDWARA, CHAND-NAGAR,WEST DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO ANIL KUMAR CHOPRA FOR ALL PURPOSES. 0040739616-1**

**I,Bhupender Chaudhary,S/O Sukhbir Chaudhary,R/O-H.No.47,Ground Floor,Block-6,Rajendra Nagar,Sector-2, Sahibabad,Ghaziabad,Uttar pradesh-201005,have changed my name and shall hereafter be known as Pinki Chaudhary. 0040739648-1**

**I,Banarsi Lal, S/O Shri Gopal Dass,R/O C-1 Ganesh Nagar,Tilak-Nagar,Delhi 110018, changed my name to Banarsi Lal DUA. 0040739600-2**

**I, Gopala Krishnan Sharda D/o Rajam Iyer Gopala Krishnan Iyer, R/O 25D, A-3, Jagriti Apartments, Sector-171, Noida, G.B. Nagar U.P.-201301 have changed my name from Gopala Krishnan Sharda to G Sharda for all future purposes. 0040739610-1**

**I, SUJATA MINHAS, W/O MOHAN CHARAN, R/O H NO-529, SECTOR-A POCKET-C VASANT KUNJ, SOUTH WEST DELHI-110070, have changed my name to SUJATA MOHAN CHARAN for all future purposes. 0070913926-1**

**I, Naresh Kumar S/o Shamburam Goel R/o H.No.1040, Sector 17,Faridabad have changed my name to Naresh Goel. 0040739592-2**

**I, KUMARI NAINIKA D/o No.406129F RANK Ex NK MOHAN SINGH R/O TA 176/1, FIRST FLOOR RIGHT SIDE FROM STAIR, GALI No.-3, TUGHLAKABAD EXTN., KALKAJI, SOUTH DELHI, DELHI-110019 HAVE CHANGED MY NAME TO NAINIKA CHAUDHARY VIDE AFFIDAVIT DATE 22.7.24 BEFORE DELHI 0070913977-1**

**I, DIPTI GUPTA W/o Rajneesh Gupta R/O H.No.85, Sector 9, have changed my name to Deepiti Gupta. 0040739592-3**

**I, Davinder Kaur Hora,W/O Manjit Singh Hora,R/O-B-22 Mansarover Garden New Delhi-110015 Have Changed My Name to Devender Kaur Permanently 0040739640-1**

**I,Kamlesh D/o Om Prakash Goyal W/O Sushil Bansal, H.No-177, FF,Pocket-5,Sector-22,Rohini, Delhi-110086 have changed my name to Kamlesh Bansal. 0040739635-3**

**I,June Lall D/O Shri Bagh Mal R/O C-1,Ganesh Nagar,Tilak Nagar Delhi-110018,changed my name to Sunita DUA. 0040739600-1**

**I,Jai Pal Singh,S/O Om Prakash,H.No - 5359/6, Street No.6,New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110007,Changed my name to Jaipal. 0040739595-1**

**I,ANJALI KASHYAP,D/O BRIJESH KUMAR KASHYAP,R/O-Gali.No.9,Vidya-Vihar, Sihani-Road,Ghaziabad,Post-Ghaziabad,Uttar Pradesh-201001,declare that name of mine has been wrongly written as ANJALI in my 10th-Class Marksheet and name of mine has been wrongly-written as KM ANJALI in my 12th-Class Marksheet & Certificate. The actual name of mine is ANJALI KASHYAP. 0040739592-10**

**I,Amandeep Singh Jaggi S/O Bhupinder Singh Jaggi R/O 2-C/40, 1ST-Floor,New Rohtak Road,Karol Bagh, W.E.A,Delhi-110005,that my children school records Jaskaran Singh and Darsh Deep Kaur my name is wrongly written/mentioned as Amandeep Singh instead of Amandeep Singh Jaggi. Which may be amended accordingly. 0040739640-5**

**I, Vijay Kumar Bajpai S/o Sh. Mayadhar Bajpai R/O 667 Ahir Mohalla Nanglioi Village Delhi-14 have changed my name to Vijay Bajpai. 0040739578-1**

**I,POOJA BABBAR alias POOJA DHAWAN D/O,RAMESH KUMAR DHAWAN W/O,PARSH BABBAR R/O,H.No-103, Pocket-F-25, Sector-3 Rohini Rajapur-Kalan, North-West, Delhi-110085,changed my-name to POOJA RAMESH KUMAR DHAWAN. 0040739582-6**

**I, Khanna Sanjeev S/o Raja Ram Khanna R/O 39B, GT Road, Yamuna Enclave, Panipat, Haryana-132103 have changed my name to Sanjeev Khanna 0070913988-1**

**I, Khanna Namita W/o Sanjeev Khanna R/O 39B, GT Road, Yamuna Enclave, Panipat, Haryana-132103 have changed my name to Namita Khanna 0070913976-1**

**I, AJAY SAXENA S/O KASHI RAM,H.No - 4649/B2/16,STREET.NO-11,NEW MODERN BUDH-BAZAR SHAHDARA,EAST-DELHI-110032,have changed my name to AJAY KUMAR,for all,future purposes. 0040739604-2**

**I, Humera Kausar Quddusi W/o Inamur Rehman R/O 385/218, Lane No.15, Ghaffar Manzil, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 have changed my name from Humera Quddusi to HUMERA KAUSAR QUDDUSI for all future purposes and legal documents. 0040739573-1**

**I,hitherto known as LOUNDU SINGH Urf RAJESH S/O RAM LAL R/O H.NO-C-61, STREET NO-1 C-BLOCK, PRATAP NAGAR, SABOLI VILLAGE, NORTH EAST DELHI-110093 have changed my name and shall hereafter be known as LOUNDU. 0040739574-1**

**I Varun Kumar S/o Rohtash Dahya R/O F-12, Swati Apartments, I.P,Extension, New Delhi-110092 have changed the name of my minor son from Havish Dahiya to Shaurya Singh Dahiya for all purposes. 0040739571-2**

**I MANJU,THE SINGLE PARENT,RESIDENT 373,SECTOR-15,SONIPAT, HARYANA HAVE CHANGED MY MINOR SON NAME FROM HARDITYA TO HARDITYA SINGH. 0040739592-6**

**I MANJU D/O RAVINDER SINGH ANTIL RESIDENT HOUSE NO-373,SECTOR-15,SONIPAT,HARYANA HAVE CHANGED MY NAME TO MANJU ANTIL. 0040739592-5**

**I Jyoti D/O, Abdul Rashid R/O Wz-1573 Tihar Village Tilak Nagar New Delhi 110018 have changed my name to Zarina. 0040739582-1**

**I Jatin Grover S/O, Bal Kishan Grover R/O A5-B/ 429, DDA Flats, Shanti Kunj, Paschim Vihar, New Delhi- 110063 have changed my name to Jatin Grover vide Affidavit Dtd: 22/07/2024 sworn before notary Rajkumar, Delhi. 0040739580-1**

**I Hitesh S/O, Ashok Kumar R/O RZ-93 Indra Park Uttam Nagar Delhi-110059 have changed my name to Hitesh Patpatia. 0040739581-1**

**I Gaurav Aggarwal S/o Ram Bhagat Aggarwal R/O A-504/4, Near A Block Gurudwara, VTC:Shastri Nagar, PO:Ashok Vihar, Sub District:Saraswati Vihar, Sub District: North West Delhi, Delhi-110052 have changed the name of my minor daughter from Pihu Aggarwal to Taavisi Aggarwal for all purposes. 0040739571-1**

**I GURPREET SINGH S/O AMARJIT SINGH R/O-28, Ground-Floor, Arjun-Nagar, Safdarjung-Enclave, South-West Delhi-110029,changed my-minor daughter's name PRIJAS to PRIJAS KAUR aged-5-Years. 0040739642-11**

**I DIVYANKA D/O ASHOK MALIK R/O Gac-024 New Town Heights Sector-86, Nawada Fatehpur(112) Gurgaon, Haryana-122004, changed my-name to DIVYANKA MALIK. 0040739642-11**

**I DIMPLE SETIA D/O GULSHAN SETIA W/O ANIRUDH SINGH R/O,H.No-24-B Gh-10, Sunder-Apartment, Paschim-Vihar, West-Delhi-110087, changed my-name to DIMPLE SETIA SINGH. 0040739642-6**

**I ATITHI VERMA D/O JITENDRA VERMA R/O,Flat-No-602 Tower-P City-Apartments, Aditya Word-City Nh-24 Ghaziabad,Kavi-Nagar Uttar Pradesh-201002 changed my name to ADITI VERMA. 0040739642-9**

**I Ishant S/O Puran Chand,House-no-361 sector -4 Rewari Haryana- 123401 have changed my Name to ISHANT KALRA Permanently. 0040739635-4**

**I AMANDA D/O NAWINDRA KUMAR SINGH R/O-9-E, CPWD-Colony, Vasant Vihar-1, South-West Delhi-110057 changed my name to AMANDA SINGH. 0040739642-7**

**I, VISHAL DAVID S/O Francis David, R/O 2515 A/27, Tughlakabad Extn., South Delhi, Delhi-110019 have changed my name to VISHAL FRANCIS DAVID for all purposes. 0040739605-1**

**I,OM PRAKASH,S/O MOHAN R/O B F-16, J.J.COLONY,MADANGIR,NEW DELHI-110062,have changed my minor daughter's name from MOHINI BANSAL to ANUSHKA VERMA,for all,future purposes. 040739640-3**

**I, SARLA DEVI, W/O DHARAM VEER SINGH R/O WZ-501, NARAINA VILLAGE, N.D-28 CHANGED MY NAME TO SARLA TANWAR. 0130043656-1**

## सार्वजनिक सूचना

**PUBLIC NOTICE**  
My clients, Mrs. Shrestha Sumbly (aged 57 years, wife of Mr. Raj Kumar, residing at B-128, Sector-122, Noida, U.P-201301, Aadhar No. 847517025517) and Mr. Raj Kumar (aged 64 years, son of Mr. M. L. Sumbly, father of Pransy Sumbly, residing at B-128, Sector-122, Noida, U.P. 201301, Aadhar No. 539114448803), hereby declare that they have disowned their son, Pransy Sumbly from all their movable and immovable assets. From this point forward, my clients shall not be responsible for any acts done by their son. The above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

**Anam Siddiqui (Advocate)**  
08215/2018

**PUBLIC NOTICE**  
My client Pashpa Saini W/o Late Sh. Pardeep Saini R/o KH. No. 681 Main Road, Blue Gate, P.O: Bhogpath, North West Delhi, Delhi 110040 severe all relations & Debar her Son Rahul Saini, S/o Late Sh. Pardeep Saini from all movable-immovable property of her husband and disrespect and immoral behaviour. And, whosoever will deal with the Rahul Saini S/o Late Sh. Pardeep Saini shall be doing so at his own risk and responsibility and my client shall not be liable for any act of the Rahul Saini S/o Late Sh. Pardeep Saini.

**Sd/-**  
**AKASH Advocate**  
Ch. No. 707, Lawyers Block, Saket Court, New Delhi

**सार्वजनिक सूचना**  
मेरी मुस्लिमकन श्रेणी शकुन्तला धर्मपती स्वर्गीय श्री बरिचक निवासी की 109, गली नंबर 3, बी-ब्लॉक, निवृत्त जीवन न्यायिक स्कूल, सावरपुर, दिल्ली, दिल्ली-94 में अपने पुत्र अशोक कुमार और उसके पुत्र अशोक कुमार कीनें सर्वोच्च न्यायिक न्यायिक दस्तावेजों, गरीबी-न्याय, लक्ष्य-न्याय और अमान्यकरण व्यवहार तथा अपराध से रोक उनके साथ अपने समस्त संबंध समाप्त करने के लिए अपने समस्त परिवार में से अशोक कुमार और अशोक कुमार के पुत्रों से मेरी अंतिम मुस्लिमकन का किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा।

**K.K. LUTHERA (Advocate)**  
Chamber No. E-211, 11th Floor, Lawyer's Chamber Block, Karkardooma Courts, Delhi

**PUBLIC NOTICE**  
To be known to all that I, Ashok Kumar S/o of Shri Himanur owner of Shop No. B-940, New Sahyog Mandir, Anandpur, Delhi, has applied for duplicate paper of the aforesaid Shop as original allotment letter, Possession letter and NOC for Water and Electricity connection has been lost. File No.F302/02/869111, An FIR No. 19557/2024 in the police station crime branch Delhi on dated 21/07/2024. Any person claiming any right or interest in the above mentioned shop, please write address/Phone no 9311717193, Dy. Commissioner of District C&J, District Office, Vikas Pathan, New Delhi-110018 within 15 days from the date of publication of this notice.

**PUBLIC NOTICE**  
My Client Smt. Seema Arora W/o Late Shri Mukesh Arora R/o House No. C-241, Gali No. 40, 60 Feet Road, Mahavir Enclave, Part - 3, New Delhi 110059, have severed all relations with her son namely Shri. Ashish Arora and have disowned & disinherited him from all her movable and immovable properties due to his untoward behaviour and conduct. Whosoever deals with him in any manner, shall do so at his/her own risk and peril.

**Anirudh Gupta (Advocate)**  
Enrll. No. D/4483/15

**PUBLIC NOTICE**  
It is hereby notified that my client Sh. Sumit Gupta S/o Sh. Narendra Kumar Gupta R/o A-1601, Golden Park, Shiv Puri, Delhi-110051 has lost the original title documents i.e. (1) Sale Deed dated 20.05.1965, (2) Partition Deed dated 22.12.2001, (3) Letter of Administration granted by Sh. Shiv Narayan Dhingra, District Judge, Delhi dated 04.02.2006 in probate case no.3392/2024, with respect to property No.B/27, Golden Park, Shiv Puri, Delhi-110051, if anyone found the above mentioned title documents/Phone contact mobile no.9810227406, 9899291241.

**Sd/-**  
**A.C. DAVID Advocate**  
304, Madras House, 6/74, Darya Ganj, New Delhi-02

**PUBLIC NOTICE**  
NOTICE is hereby given that my client I P Singh Bhasin S/O Late Sd. Manna Singh intend to sell his property situated at Punjabi Bagh west bearing plot no 47 at West Avenue Road, New Delhi-110026. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect of the said property, is hereby required to make the same in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at within 15 days from the date of publication hereof, failing which claims if any shall be deemed to have been considered given up or waived.

**Anurag Patilwal (Advocate)**  
D-728, Street No.4, Shakapur New Delhi-110092

**PUBLIC NOTICE**  
Know by public at large that my client Sh. Ramesh Kumar, S/O L. Sh. Assa Singh, currently residing at WZ-298, upper ground floor, gali no.4, Jangra, Jangra, Gurgaon, Delhi-110034, aadhar card no. 8713-4557-5935 has disowned/ debarred his one of the sons, Ashish Dhangra, aged of WZ-23/76, Mahalinda park, Bahadur Bagh, Delhi-110034, having aadhar card no. 5102-4047-7485, from all his all movable and immovable properties due to misconduct. Any persons deal with them, then my client shall not be responsible at all.

**Sd/-**  
**SANDEEP KUMAR Advocate**  
Ct. No. 214, D-Block, Hnd Floor, Karkardooma Court, Delhi-110032

**PUBLIC NOTICE**  
Be it known to world wide at large that I, Brij Lal s/o Bajrath r/o G-1 Block 36, Gali No.2, Saket Enclave, Mohan Garden, New Delhi - 110059, have revoked public notice dated 20/08/2020, published in Newspapers "Indian Express" and "Jansatta", regarding disownment and disinheretance of my son namely Ajay Kumar Yadav, from all my movable & immovable properties, w.e.f 20.07.2024. Henceforth, my son and his wife, their legal heirs or any person claiming through them, will have claim, right, title and interest in my movable and immovable properties as per applicable law. Manoj Kumar, Advocate Chamber No. 114, 1<sup>st</sup> Floor, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054

**PUBLIC NOTICE**  
My clients RITA and HER SON SUNIL SHARMA AXIL SARABJI and HER DAUGHTER RAINI RESIDENT OF D-434 PEERAGARI CAMP SHAKUR BASTI DEPOT NOW NORTH WEST DELHI-110059 HAVE REMOVE THEIR RELATIONSHIP AND EXPEL THEIR HUSBAND/FATHER AJAY SHARMA AGE 59 YRS. D-434 PEERAGARI CAMP SHAKUR BASTI DEPOT SO NORTH WEST DELHI-110056 FROM ALL THEIR MOVABLE AND IMMMOVABLE PROPERTIES BECAUSE HE IS OUT OF THEIR CONTROL. IF ANYBODY DEALS WITH HIM, HESHE WILL DO SO ON HISHER OWN RISK.

**PRAGATI GAHLAUT (Delhi-54)**  
OFFICE-C-62, C11 LAWYERS CHAMBERS 152-HAZARI DELHI-54

**PUBLIC NOTICE**  
Notified that my client(s) Mohd Farukh So Nahi Akram (D/o Shabjida Khatoon W/o Md Farukh both R/O House No.688, Block-D, J.J Colony, Bhalawa Delhi-110042, has severed relations from her son Mohd Aftab and his wife Amina Praveen and their siblings, due to their cruel and harassing behaviour towards my above named clients, from all our movable & immovable properties. Any person dealing with him/her they will do at their own cost & risk and my clients should not be responsible for them. If any,

**SAURABH GUPTA (Advocate)**  
Enrll. No. D/369/2011

**PUBLIC NOTICE**  
Be it known to all that my clients Mr. Rishi Kumar S/o Late Mr. Ran Singh and Meenu W/o Mr. Rishi Kumar, R/o J-295, Dakshin Park, Ambekar Nagar, New Delhi-110062, have debarred, disowned their daughter namely Ms. Dakshita Rishi from their all movable and immovable properties and severed their al relations with her due to her disobedient, ill-treatment and hostile behaviour towards my clients and their other family members and she (Dakshita Rishi) is not under their control. My clients shall not be responsible for any of her act, conduct and deeds whatsoever in future of their daughter Dakshita Rishi. Anybody dealing with above said person shall be doing so at their own risk.

**Ramesh Kumar (Advocate)**  
Enrolment No. D/102797/R Chamber No. 325, Saket Court Complex, New Delhi -110017

**PUBLIC NOTICE**  
Be it known to all concerned that my clients Anis Ahmad S/o Lal Mohammad and his wife Smt. Shamma Parveen W/o Anis Ahmed, both R/o A-37, Mangs Ram Park Puri, Bahd Vihar

## खबर कोना

अवैध पार्किंग और  
अतिक्रमण के खिलाफ  
कार्रवाई के निर्देशजनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

महापौर शैली ओबेरॉय ने सोमवार को करोलबाग जेन के वार्ड संख्या-86 में पूर्वी पटेल नगर और पश्चिमी पटेल नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया और क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान महापौर ने निगम अधिकारियों को अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि अनधिकृत पार्किंग की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कहीं पर भी अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण न हो।

जामिया विवि में शाहिद  
खान मुख्य कुलानुशासक  
और सुरक्षा प्रभारी नियुक्तजनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने मोहम्मद शाहिद खान को तत्काल प्रभाव से मुख्य कुलानुशासक और सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद शकील द्वारा विज्ञान संकाय के अतीकुर रहमान को तत्काल विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक और सुरक्षा प्रभारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के बाद की गई है।

प्रसाद नगर इलाके में  
तीन झपटमार गिरफ्तार

नई दिल्ली, 22 जुलाई (संवाददाता)।

प्रसाद नगर पुलिस टीम ने तीन शांति झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बदमाशों में से एक रोहित उर्फ पांडा पहले से भी दो मामलों में शामिल है। जबकि उसका साथी मिहिर एक आपराधिक मामले में सलिस है। जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक, तीन जुलाई को प्रसाद नगर इलाके में झपटमारी की एक वारदात हुई थी। इसमें तीन लोगों ने बापांनगर इलाके में एक शख्स से मोबाइल छीन लिया था।

ज्ञान और समृद्धि का  
संदेश देती हैं  
पुस्तकें : अमिताभ कांतजनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

लेखक और जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करती है।

कांत पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'द रीडर्स कांक्लेव' के नाम से माटी ट्रेस्ट के पाठक समागम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पाठक समागम के पहले संस्करण में कारपोरेट प्रबंधन, जीवनी, यात्रा वृत्तान्त, इतिहास, आध्यात्मिकता से लेकर कथा साहित्य, बाल कथा और कविता तक लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है। माटी के संयोजक आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा, हम पाठकों को मूल स्रोत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी।

मामले को लेकर दो  
वकील आपस में भिड़े

नई दिल्ली, 22 जुलाई (संवाददाता)।

लक्ष्मी नगर थाना स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट परिसर में शनिवार को दो वकील एक मामले को अपने हाथ में लेने के लिए आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर लात और झूठे से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग निवारक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

मेट्रो के खंभे से टकराई डीटीसी  
बस, महिला की मौत; 34 घायल

मादीपुर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की इलेक्ट्रिक बस का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे मेट्रो के खंभे से टकरा गई। जिसके कारण बस में बैठे करीब 34 यात्री घायल हो गए। हादसे में 45 साल एक महिला की मौत हो गई।

इस दुर्घटना में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूट नंबर 939 की यह बस मंगोलपुरी से आइएसबीटी आनंद विहार तक चलती है। यह हादसा मादीपुर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुआ।

पश्चिमी जिला पुलिस उपयुक्त विचित्र वीर ने बताया कि पंजाबी बाग थाने को सोमवार सुबह सात बजेकर 42 मिनट पर रोहताक रोड पर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट बस दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां प्रारंभिक जांच से पता चला कि मंगोलपुरी और आनंद विहार के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम के (डीटीसी) बसें को इलेक्ट्रिक बस मेट्रो खंभे से टकरा गई। उपयुक्त ने कहा कि बस के अचानक ब्रेक



लगाने के कारण एक आटो रिक्शा और मोटरसाइकिल भी पीछे से बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में चालक और कंडक्टर समेत कुल 34 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि बस में सवार 45 वर्षीय महिला यात्री को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक अन्य 55 वर्षीय यात्री फिलहाल आइसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) में है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 34 घायलों में से कुछ का इलाज महाराजा अग्रसेन अस्पताल में जारी है, जबकि शेष घायलों को मोती नगर स्थित आचार्य भिषु अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस उपयुक्त ने कहा कि पंजाबी बाग पुलिस

दुर्घटना से बचने के लिए मोड़ी बस डीटीसी के एक अधिकारी ने दावा किया कि बस अपनी निर्धारित लेन में चल रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार और एक आटोरिक्शा चालक अचानक दाएं मुड़ गए। दुर्घटना से बचने के लिए बस चालक भी दाएं मुड़ा लेकिन संतुलन खीने के बाद बस मेट्रो खंभे से टकरा गई। दुर्घटना के बाद काफी देर तक उस सड़क पर यातायात जाम की स्थिति बन गई।

थाने में कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बस की रफ्तार काफी तेज थी

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से चालक उसपर नियंत्रण नहीं कर रख सका। बस और आटो को क्षतिग्रस्त हालत में पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने धारा 281, 125ए और 106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर चालकों और घायलों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगल रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सके।

सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत,  
न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ाईजनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

अदालत ने शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 26 जुलाई तक बढ़ा दी। राजज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया, जब सिसोदिया को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और संबंधित धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने कविता के खिलाफ  
आरोप पत्र पर लिया सज्ञान

अदालत ने शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को सज्ञान लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर ध्यान दिया और कहा कि मामले में उनके खिलाफ आरोप बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने सीबीआइ को कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।

खुद को गोल्डी बराड़ बताकर  
बताकर मांगी रंगदारी, दो गिरफ्तारजनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पुलिस ने खुद को गोल्डी बराड़ बताकर रंगदारी मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ इस संबंध में पिछले 20 जुलाई को थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान रोहिणी सेक्टर-16 निवासी मनोज उर्फ बंटी (40) और रोहना, हरियाणा निवासी अनिल सिवाच (43) के रूप

में हुई है। रोहिणी जिला पुलिस उपयुक्त गुडकबाल सिंह सिद्ध ने सोमवार को बताया कि पिछले 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे एक व्यक्ति को अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया और रंगदारी मांगी। फैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उपयुक्त ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई। फोन रिकार्ड की जांच के बाद अनिल सिवाच को गिरफ्तार किया

गया और बाद में रविवार को उसके सहयोगी मनोज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता का मनोज के साथ रूप को लेकर विवाद था। ऐसे में मनोज ने अपने दोस्त अनिल के साथ मिलकर यह साबित रची। पुलिस ने बताया कि अनिल एक ई-कामर्स कंपनी के माध्यम से आनलाइन उत्पाद बेचने का काम करता है जिसके लिए वह फोन करने के खातिर अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल करता है।

3<sup>rd</sup> EDITION उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपोजे एंड कांफ्रेंस

# UFSEC

औद्योगिक सुरक्षा (एचएसई), अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर एक विशेष प्रदर्शनी और सम्मेलन

**24<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> जुलाई 2024**

## उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फायर एंड सेफ्टी एक्सपोजे एंड कांफ्रेंस

**अवश्य पधारें!**

सुरक्षित कार्य है कर्तव्य हमारा, सुरक्षित जीवन से जुड़ा है भविष्य हमारा, आइये, आग को दूर रखने के लिए और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए "रास्ता प्रज्वलित करें"

क्र. सं.	विवरण	30.06.2024 को सम्मान विभागी (समीक्षित)	30.06.2023 को सम्मान विभागी (समीक्षित)	31.03.2024 को सम्मान वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	685942	585659	2511987
2	अवधि का निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों के पूर्व)	86247	34666	256885
3	अवधि का कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	86247	34666	256885
4	अवधि का कर पश्चात समंजित निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	56530	22493	167155
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि सहित) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	संदर्भ नोट - 2		
6	प्रदान ईक्विटी शेयर पूंजी	1195596	1195596	1195596
7	आरक्षित निधि (आरक्षित निधि के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	1226027	1084444	1226027
8	प्रतिभूति प्रोविडन खाता	362571	362571	362571
9	निवल मुल्य	1624551	1420661	1611085
10	चुकाता ऋण पूंजी / बकाया ऋण	0.07	0.09	0.08
11	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर			
12	ऋण ईक्विटी अनुपात	1.07	0.87	0.93
13	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थागित परिचालनों के लिए)			
14	1. मूलभूत :	0.45	0.19	1.40
15	2. अनुकूल :	0.45	0.19	1.40
16	पूनी प्रविष्टि आरक्षित निधि			
17	विशेष प्रविष्टि आरक्षित निधि			
18	ऋण चुकोती करके अनुपात			
19	खान चुकोती करके अनुपात			

नोट : 1. उक्त विवरण सेवा अधिनियम 2015 (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज विवरणों के लिए विनियम परिणामों के तहत प्रकृत का स्वर है। विवरणों/समाहों के लिए विनियम परिणामों का पूर्ण आरूप स्टॉक एक्सचेंजों को वेबसाइट (www.seindia.com) और www.bsindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर उपलब्ध है। 2. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि ईड-एस अभी तक बैंक पर लागू नहीं हुआ है।

यूको बैंक कृते

स्थान : कोलकाता दिनांक : 22 जुलाई, 2024

डि. विजयकुमार निवृत्ति कावले  
कार्यवाहक निदेशक

डि. राजेंद्र कुमार राय  
कार्यवाहक निदेशक

डि. अरुणा कुमारी  
उपनिर्देशक एवं सीईओ

डि. अरुण कुमार  
उपनिर्देशक

www.ucobank.com

### खबर कोना

#### फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने चुराए

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

जलवायु विहार स्थित महिला मीडियाकर्मी के फ्लैट का ताला तोड़कर चोर सोने के गहने समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिस समय फ्लैट में चोरी हुई, तब पीड़िता अपने गृह जनपद कानपुर गई हुई थी। महिला की शिकायत पर थाना सेक्टर-20 पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता श्याम वाजपेयी ने बताया कि बीते दिनों वह किसी काम से कानपुर अपने घर गई हुई थी। 18 जुलाई की सुबह पड़ोस में रहने वाली महिला का फोन आया, उन्होंने फ्लैट का ताला टूटा होने व चोरी के बारे में बताया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों को फ्लैट में सामान रखे होने की सटीक जानकारी थी।

#### किसानों का एलान, 15 अगस्त को होगी ट्रेक्टर रैली

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के बजट सत्र के बीच सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा व उसके सहयोगी संगठनों ने 15 सितंबर और 22 सितंबर को हरियाणा में किसान महापंचायत करने का एलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा की सोमवार को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 अगस्त से 22 सितंबर तक होने वाले आंदोलन कार्यक्रम जारी किए गए। इनमें से 1 अगस्त को पुलला दहन कार्यक्रम और 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों में ट्रेक्टर रैली के अलावा दो बड़ी किसान रैली (15 सितंबर को हरियाणा के जींद में और 22 सितंबर को हरियाणा के पीपली में बड़ी रैली) का एलान किया गया है। इसके बीच शंभू सीमा पर हुए आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर 31 अगस्त को वहां किसान फिर पहुंचेंगे। सोमवार को हुई बैठक में देशभर से 150 से अधिक संगठनों के नेताओं ने भाग लिया।

#### सोहरखा गांव में करंट लगने से युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

सोहरखा गांव में बिजली सही करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सोहरखा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। थाना सेक्टर-113 प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर किसी ने अभी तक शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसा उस समय हुआ जब जितेंद्र बिजली सही कर रहा था।

#### खाली प्लाट में मिला शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

सेक्टर-96 स्थित सुपरटेक इमारत के पास सोमवार को खाली प्लाट में 30 से 35 साल के उम्र के एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस का दावा है कि मृतक के शरीर पर घोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव के पास से ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, जिससे उसकी पहचान की जा सके। मृतक के बारे में जांच पर काम चलाया जा रहा है।

#### राष्ट्रगान गांने के लिए मजबूर किए व्यक्ति की मौत मामले पर फैसला आज

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गांने के लिए मजबूर किए गए 23 वर्षीय व्यक्ति की मौत की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) से कराने के अनुरोध पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी मृतक फैजान की मां की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएंगे। एक वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिमों के साथ राष्ट्रगान गांने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए दिखाया गया है।

## श्रद्धा वालकर हत्याकांड महीने में सिर्फ दो बार सुनवाई की पूनावाला की याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने वकील को बचाव की तैयारी के लिए उपयुक्त समय देने के लिए हर महीने केवल दो बार सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि यह

अनुरोध केवल मुकदमे को लंबा खींचने का एक साधन मात्र है। अदालत ने अंतिम संस्कार के लिए वालकर की अस्थियां तुरंत जारी करने से भी इनकार कर दिया। आरोपी के साथ सहजीवन में रहने वाली वालकर की कथित तौर पर 18 मई, 2022 को पूनावाला ने गला घोटकर हत्या कर दी थी। पिछले साल जनवरी में दिल्ली पुलिस द्वारा

### हड्डियां देने से कोर्ट का इनकार



और कई बाहरी गवाहों की गवाही के लिए

दाखिल 6,629 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, पूनावाला ने कथित तौर पर वालकर के शरीर के टुकड़े किए, उसे फ्रिज में रखा और पकड़े जाने से बचने के लिए कई दिनों तक शहर भर में सुनसान जगहों पर टुकड़ों को ठिकाने लगाया। बाद में शव के अंग खोजे गए। उन्होंने कहा कि अभियुक्त का यह अनुरोध कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के

कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता की हड्डियों को दाह संस्कार के लिए तुरंत जारी करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गवाहों द्वारा पहचान के लिए अस्थियों की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में दिए गए एक आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कवकड़ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 212 गवाहों में से 134 की गवाही हो चुकी है

लिए एक महीने में सुनवाई की केवल दो तारीखें तय की जाएं, मुकदमे को लंबा खींचने का एक साधन प्रतीत होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पुलिस के गवाहों की लंबी गवाही दर्ज करने के लिए काफी समय की आवश्यकता है।

## सोमनाथ भारती की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा गलतियों से भरी है याचिका, पहले इसे सुधार कर लाइए

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलतियों से भरी है। कोर्ट ने उनसे एक संशोधित याचिका दायर करने को कहा। न्यायमूर्ति पीएस अरोड़ा ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि याचिका में मुद्रण संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिससे इसमें दिए गए कथनों को समझना मुश्किल हो गया है। अदालत ने भारती को संशोधित याचिका

दायर करने के लिए 10 दिन का वकत दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की। जब भारती के वकील ने अदालत से याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया, तो न्यायाधीश ने कहा कि बहुत सारी गलतियां हैं। पहले याचिका को ठीक करें। मैं इस तरह नोटिस जारी नहीं कर सकता। मैं बस इसे स्थगित कर दूंगा। कृपया एक संशोधित याचिका दायर करें। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दायर याचिका में स्वराज, उनके चुनावी एजेंट तथा अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है।

## 'सेंट्रल विस्टा' के संबंध में अदालत ने वक्फ बोर्ड से कहा जब केंद्र कार्रवाई करे तो याचिका दायर करें

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि जब भी केंद्र 'सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास परियोजना के संबंध में उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम कुमार कौरव ने कहा कि परियोजना को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिली हुई है और उन्होंने बोर्ड से 2021 में दायर अपनी याचिका वापस लेने को कहा। बोर्ड ने इस याचिका में क्षेत्र में अपनी छह संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था।

### न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को वापस ले लीजिए। हम मामले को उलझाना नहीं चाहते।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वक्फ बोर्ड यह नहीं कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को खत करना होगा बल्कि वह केवल यह आशवासन चाह रहा है कि उसे उसकी संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को वापस ले लीजिए। हम मामले को उलझाना नहीं चाहते। जब भी वे कोई कार्रवाई करेंगे, आप आ सकते हैं।

## नोएडा में महंगे वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

मांग पर महंगे वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना सेक्टर-113 पुलिस ने सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर अलग-अलग जगहों से कुल दस कारें बरामद

की हैं। गिरोह पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलग-अलग थानों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के बदमाशों ने अब तक 200 से ज्यादा कारों की चोरी दिल्ली-पनसीआर समेत अन्य राज्यों में की है। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को डीसीपी नोएडा ने 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

### तैयारी

## दिल्ली सरकार का दावा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए जाएंगे 185 शिविर

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली में इस बार कांवड़ियों के स्वागत के लिए 185 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी कांवड़ शिविर जलरोधी, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, शौचालय, फर्नीचर सहित तमाम सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली सरकार कांवड़ियों के सहूलियत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यह दावा राज्यस्व मंत्री आतिश ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 185 कांवड़ शिविरों के जरिए कांवड़ियों के लिए सबसे बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में हमारे शिविरों में चिकित्सा सुविधा, साफ-पानी,

### दिल्ली सरकार का दावा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी

## दिल्ली सरकार का दावा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए जाएंगे 185 शिविर

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

शौचालय, फर्नीचर सहित तमाम सुविधाएं दी जा रही है। बता दें कि, दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन 25 जुलाई के बाद से होगा और इससे पहले सभी कांवड़ शिविर पूरी तरह तैयार होंगे। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली व शाहदरा जिले से कांवड़ियों का आगमन होता है। ऐसे में इन तीनों जिलों में कांवड़ियों की सुविधा के लिए सबसे अधिक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 38 शिविर शाहदरा जिले में लगाए जा रहे हैं। उत्तरी-पूर्वी, सेंट्रल और पूर्वी दिल्ली में क्रमशः 29, 22 व 19 शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जून से ही कांवड़ शिविरों को लेकर राज्यस्व विभाग की तैयारियां जारी हैं और लगातार विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है।

## एसीबी ने अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अस्पतालों में मानव बल/सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) मधु वर्मा ने कहा कि तय संख्या से कम कर्मियों के

तैनाती, अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती, ईएसआइ और भविष्य निधि के फर्जी दावे, नियोक्ताओं द्वारा रिश्तत की मांग और सरकारी धन के गबन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिकारी भी निजी एजेंसियों के साथ आपराधिक साजिश में संलग्न हैं। अस्पतालों में सुरक्षाकर्मियों को तैनाती की गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) मधु वर्मा ने कहा कि तय संख्या से कम कर्मियों के

## नोएडा में मंदिरों के आसपास रही चाक-चौबंद सुरक्षा

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 22 जुलाई।

सावन के पहले सोमवार के मौके पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुबह पांच बजे से ही प्रमुख मंदिरों के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। मंदिरों में भक्तों को जलाभिषेक में भीड़ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रमुख मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार लगी। कई जगह ड्रॉन कैमरे से मंदिर परिसर में होने वाली हर

गतिविधि की निगरानी की गई। सोमवार को एडीसीपी नोएडा मनीष मिश्र व एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने सुबह मंदिर शिवालयों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीसीपी मनीष मिश्र ने बताया कि सावन मास को लेकर मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। सावन के पहले सोमवार से ही लोग मंदिर शिवालयों में जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस बाबत मंदिरों और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

## निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुरेंद्र कोली को नोटिस सौंपना सुनिश्चित करें एसएसपी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2006 के निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को नोटिस सौंप दिया गया है। शीर्ष अदालत में कोली को बरी किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार सुजाता सिंह ने कहा कि निठारी हत्याकांड के एक पीड़ित के पिता पप्पू लाल की अपील पर न्यायमूर्ति वीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी नोटिस सुरेंद्र कोली को नहीं दिया गया है, जो गाजियाबाद की डासन जेल में बंद है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी से भी यह बात स्पष्ट करवाई जाए और इसके बाद एसएसपी के माध्यम से प्रतिवादी सुरेंद्र कोली को नोटिस

19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।



जारी किया जाए। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए चार सितंबर को सूचीबद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि बीते 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। यह सनसनीखेज हत्याकांड 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में मोनिर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था। पंधेर भी इस मामले में आरोपी था।



## बरी किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर अदालत ने सज्जन कुमार से जवाब मांगा

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को कुमार से जवाब मांगा। कुमार दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फिलहाल तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुमार को बरी करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है, जिसपर

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कुमार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने आदेश के खिलाफ एक गवाह शीला कौर की अपील पर भी कुमार को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर, 2023 को विशेष न्यायाधीश गीताजलि गोयल ने कुमार को संदेह का लाभ देते हुए मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों - वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी बरी कर दिया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या व दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा था।

## प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन केंद्र बंद करने वाले पेट्रोल पंपों पर हो सकती है कार्रवाई

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली सरकार उन पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से असंतुष्ट होकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्रों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 'डेल्टा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन' (डीपीडीए) के आह्वान पर करीब 600 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केंद्र करीब एक सप्ताह से बंद हैं।

डीपीडीए ने बताया कि प्रस्तावित शुल्क वृद्धि केंद्रों के परिचालन में आने वाली लागत के अनुकूल नहीं है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग उन डीलर के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है, जिन्होंने इन केंद्रों को बंद कर दिया है और जनता को असुविधा हो रही है। इन केंद्रों के परिचालन के लिए एक अलग लाइसेंस जारी किया गया है। हम ईंधन स्टेशनों की एक सूची तैयार कर रहे हैं और सरकार सोच रही है कि क्या पीयूसीसी केंद्र संचालित करने के लिए उन्हें दिए गए लाइसेंस को निलंबित किया जाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक, सूची परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट को दिखाई जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि उपभोक्ताओं के साथ-साथ पेट्रोल पंप मालिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर की गई है।



## विकास का अर्थ

आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखाजोखा पेश किया जाता है। इसी आधार पर आगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। इस वर्ष चूंकि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। भारत की कुल श्रमशक्ति में से सत्तावन फीसद स्वरोजगार में लगी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदशन भी बेहतर रहेगा। इस वर्ष विकास दर के साढ़े छह से सात फीसद रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती हैं।

पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। यों पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक बजटीय प्रोवधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में नौ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वित्तमंत्री ने कहा है कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक़्त है। अगले वित्तवर्ष में बजट घाटा घट कर साढ़े चार फीसद तक रह जाने की संभावना जताई गई है। नाए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिटाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जाहिर है, आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा।

हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल, आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नजर नहीं आता। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर नजर आती है, मगर आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नजर नहीं आते। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रयशक्ति घटने की वजह से परेशान हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कटिन बना हुआ है। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा, तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी।

## खेती और खुदकुशी

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर यहां के किसान आज भी कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से भिरे हुए हैं। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की एक रपट के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राज्य में 1,267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा थे। इसी तरह वर्ष 2021 में कृषि कार्यों में लगे 10,881 लोगों और 2020 में 10,677 लोगों ने अपनी जान दे दी। किसानों की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कर्ज या आर्थिक संकट को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि इन आर्थिक परेशानियों के भी कई स्तर हैं। मसलन, प्राकृतिक आपदा, कर्ज का बोझ, फसलों की बढ़ती लागत, घटती आय और फसलों के उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र सरकार की रपट में कहा गया है कि राज्य में पिछले छह माह में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में सामने आए हैं।

बहुत से किसान खेती के लिए बैंक और साहूकारों से कर्ज लेते हैं और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाए या उत्पादन कम हो, तो उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। उर्वरक, खेती के लिए उपकरण और सिंचाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लिहाजा, किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़नी स्वाभाविक हैं। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। दूसरी ओर, उद्योग जगत के ऋणों के प्रति सरकार के नजरिए में जो नरमी देखी जाती है, वह किसानों के लिए नहीं दिखती। ऐसे में किसानों की समस्याओं की जटिलता अगर उन्हें अंतर्गत है कगार पर ले जाती है तो इसे एक नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाने जरूरत है, अन्यथा यह स्थिति और जटिल होगी।

# बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियां

बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

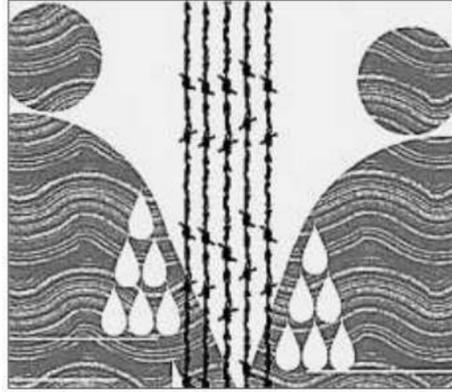
### ब्रह्मदीप अलूने

बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

बांग्लादेश भारत की 'एकट ईस्ट पालिसी' का अभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च, 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को उस सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया, जो भारत की अखंडता को रक्षा के लिए बेहद ख़ास माना जाता है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले से प्रभाव में हैं। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल का इस प्रकार निर्माण किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया है। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग डेढ़ अरब अमेरिकी डालर हो गया है। लगभग सात सौ चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बांग्लादेश चीन की 'वन बेल्ट वन परियोजना' का प्रमुख साझेदार बन गया है और इसे 'विजन 2041' और 'स्मार्ट बांग्लादेश' के सपने के साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है।

बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ उच्च संसाधनों की आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आसान आदान-प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उसकी युआन कूटनीति का परिचायक है। शेख हसीना के 'विजन 2041' की शुरुआत करीब डेढ़ दशक पहले हुई, चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए गए। 2009 में, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनने के क्षमता निर्माण पर आधारित है।

इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि 5जी उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रन के संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रहे



हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगी है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से

हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति हो गयी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है, अब चीन ने तीस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई है। तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगी और उसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा।

प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस 'विजन 2041' पर काम कर रही हैं, उसमें उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नजर आती है। इस योजना के चार मुख्य आधार तय किए गए हैं—

सुशासन, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज- नीति के चलते दुनिया के कई देशों में सुशासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उबार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुविधापूर्ण है ही, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है।

# अहं की दीवारें

### प्रदीप उपाध्याय

आजकल जिधर देखें, वहां 'मैं' का बोलबाला दिखता है। यह भाषा का नहीं, व्यक्ति का 'मैं' है। इस 'मैं' में ही सब कुछ है, दूसरा तुच्छ, दोगम दर्जे का हो जाता है। इसमें अहंकार परिलक्षित होता है, दंभ दिखाई देता है, स्वयं के श्रेष्ठ होने का मिथ्या अभिमान आभासित होता है! जबकि प्रत्येक मनुष्य में गुण-अवगुण का समिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसमें अपने गुणों को जानने-समझने का माद्दा होगा, वह अपने अवगुणों से स्वयं ही विरत हो जाएगा। जब कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तब स्वयं की श्रेष्ठता का कैसा मिथ्याभिमान! पद-हैंसियत, संपन्नता किसी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बनाते। अगर कोई अपने पद, अपनी हैंसियत, आर्थिक संपन्नता के आधार पर श्रेष्ठता का घमंड करता है, तो यह उचित नहीं है। श्रेष्ठोजन अपनी बुद्धि के साथ विवेक से संचालित होते हैं, जिसके कारण उनमें अहंकार का भाव जागृत हो ही नहीं सकता। विवेकशून्य व्यक्ति ही अहंकार के वशीभूत होकर अपने सामने दूसरों को निकृष्ट मान बैठता है, जबकि व्यक्ति अपने गुणों और अपने अच्छे स्वभाव तथा व्यवहार के कारण ही सम्मान का अधिकारी होता है।

अपनी श्रेष्ठता का बखान करने वाले अहंकारी ही होते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग, विचार या फिर पंथ की श्रेष्ठता तभी मान्य हो सकती है, जब अन्य को यह महसूस हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो और उन्हीं के द्वारा यह बात कही जाए। दबाव, हिंसा या अनैतिक आधार पर उच्चता साबित नहीं हो सकती है। यह अहंकार की अभिव्यक्ति ही होगी। अहंकारी मन किसी भी तरह के सत्य को सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अहंकार के साथ झूट है, फरेब है। किसी ने कहा भी है कि 'अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश, न मानो तो देख लो, कौरव, रावण और कंस'।

कहा गया है कि अहंकार राजा रावण का भी नहीं राज। त्याग, सहनशीलता, विनम्रता के गुणों के कारण राजा राम पूजे जाते हैं, लेकिन आज के दौर में जहां किसी को कोई पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई नहीं कि उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने से नीचे वाली स्थिति के व्यक्तियों की तौहीन करने लगता है, अपमानित करने लगता है। जबकि व्यक्ति के बड़ा होने पर उससे बड़प्पन की दरकार रहती है, न कि उसके अहंकारी हो जाने की।

निस्संदेह जब व्यक्ति में अहंकार कूट-कूट कर समा जाता है, तब उसकी सोचने-समझने की क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। यानी अहंकारी व्यक्ति अच्छे-बुरे में भेद करने की क्षमता खो देता है। उसे लगता है कि जो वह कह रहा है या जो वह

कर रहा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।

अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है, दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है, वह स्वयं है। उस पर 'मैं' का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है, वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा और पराभव है। अहंकारी मन अंतर्मन से उद्धेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत। जो भी सामने आ जाए, उसे बहा ले जाने को उद्धत या फिर अपने में समा लेने की चाहत। अपने प्रति विरोध का स्वर कुचल देने की धृष्टता। जबकि इसके विपरीत जहां 'हम' का भाव समाहित हो जाता है, वहां सहयोग है, सद्भाव है। सुख है, मन झील के ठहरे हुए जल-सा शांत और निर्मल भाव में रहता है। कहीं कोई उद्वेग नहीं, कहीं कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं, सभी के प्रति समभाव, सद्भाव। दूसरों के अस्तित्व का सम्मान, उनके विचारों के प्रति कोई राम-द्वेष नहीं। सह-अस्तित्व की आकांक्षा यहीं आकर बलवती होती है।

अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को स्वीकार करने वाला कभी अहंकार नहीं करता। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक और एक ग्यारह होते हैं। उस एक को भी मान्यता समवत होकर ही मिल सकती है। एक अकेला कभी भारी नहीं हो सकता। सेनापति भी

अहंकारी मन अंतर्मन से उद्धेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत।

यहां एक उद्धरण जोड़ना भी प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जब उसका जनाजा निकाला जाए, तब उसकी दोनों हथेली बाहर की ओर लटकई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ईंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को अहंकारी,

अभिमानी, घमंडी होना चाहिए? नहीं। जीवन बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है। मिलजुल कर, सामंजस्य के साथ रहना सीखना चाहिए। त्याग, सहनशीलता, सहानुभूति, दया, ममता, वात्सल्य के गुणों से लबरेज रहकर लोगों के दिलों को जीतें, न कि घमंड, अहंकार में चूर रहकर अपनों से भी दूर हो जाएं। जीवन तभी संवरेगा और खुशहाल होगा, जब हम अपना अहंकार छोड़कर 'मैं' के स्थान पर 'हम' की भावना से संचालित होकर कर्म करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है- 'बूढ़-सा जीवन है ईंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां न बादशाह चलता है, न इस्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का/ यहां सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है।'

### दिखावे के समारोह

पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में आई जेफरीज की एक रपट के मुताबिक, भारत में हर विवाह पर औसत खर्च 12.5 लाख रुपए है। भारतीय लोग शिक्षा से ज्यादा वैवाहिक कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। हकीकत यह है कि अब शादियां भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते खोखले। शादी में किए जाने वाले खर्च को व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाने लगा है और लोग शादियों में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। शाही शादियों के पीछे एक बड़ा कारण उपभोक्तावाद की बढ़ती प्रवृत्ति और दहेज की लालसा है। जिस तरह से शादियों में दहेज का लालच बढ़ रहा है, उससे यह सवाल उठेगा कि क्या विवाह अपने स्वार्थ के लिए किया गया एक समझौता है। इसके अलावा, अब शादियों को दिखावे और प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाने लगा है। परंपराओं के मुकाबले सब कुछ पूरी तरह बाजारवाद से प्रभावित है। सवाल है कि हमें इससे क्या प्राप्न हुआ, तो जवाब है बेतहाशा भोजन की बर्बादी, बढ़ती दहेज संस्कृति, लोगों पर बढ़ता कर्ज, बेटियों के जन्म को समस्या के रूप में देखा जाना। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

- सौरभ बुदेल, भोपाल, मप्र

### प्रकृति प्रथम

कुछ दिनों पहले तक उत्तर भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे थे। लू सैकड़ों जिंदगियां लील गई। अब वारिश कहर बन कर आई। बाढ़, बिजली गिरने, इमारतों के ढहने, जलभराव आदि से लोग मरने लगे। असल में मौसम के यह रौद्र रूप मानव निर्मित है। इसके लिए बढ़ती आबादी, अधाभुंध विकास, संसाधनों के अत्यधिक दोहन वाली उपभोक्तावादी संस्कृति, मानव का खुद को धरती का मालिक और सर्वश्रेष्ठ प्राणी

### बढ़ती खाई

प्रतिभाएं हर व्यक्ति में जन्म से ही निहित होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बचपन से ही वह व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ललक लिए रहता है। हालांकि ऐसी प्रतिभाएं तब धरी की धरी रह जाती हैं जब उसे अपनी प्रतिभाओं के दोहन के लिए संसाधनों के केंद्रीकरण का सामना करना पड़ता है। आक्सफेम के एक सर्वे के अनुसार मात्र एक फीसद लोगों के पास चालीस फीसद संसाधन और पचास फीसद लोगों के पास

### बिहार की बिसात

सन 2005 से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र में रही भाजपा और कांग्रेस सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार की राजनीति एक बार फिर सुखियों में है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, जबकि जनता दल (एकी) ने विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की बात कही है। इस मांग के समर्थन में राजम में शामिल लोक जनशक्ति और हिंदुस्तान आवाग पार्टी ने भी सुर में सुर मिलाया है, लेकिन इस मांग का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह मांग इतनी आसानी से केंद्र सरकार पूरी करने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कुछ हद तक राजनीतिक दबाव की परिभाषा में भी आती है। हालांकि देश में कुल मिलाकर ग्यारह ऐसे राज्य हैं, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com



## कला

रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर भगवान शिव की कलाकृति बनाई।

## बोल

ब्रिटेन की नई सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह यूक्रेन की सेना को रूस के और भीतरी इलाकों पर हमला करने में मदद करे, ताकि उनके देश पर रूस के घातक मिसाइल हमलों को रोका जा सके।  
- जैलेस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति



## बोल

सिख अल्गाववादी गुपतवंत सिंह पन्नु की हत्या के प्रयास की साजिश के आरोपों के संबंध में भारत के साथ बातचीत सम्मानजनक और प्रभावी रही है, क्योंकि यह बंद दरवाजों के पीछे ही रही है। - जेक सुलिवन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए)



## सम-सामयिक

## बांग्लादेश में हिंसा : सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों पड़ी

## जन्सत्ता संवाद

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द करने की मांग के मुद्दे पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक घटनाओं के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को रद्द कर दिया है। अब तक यहाँ सरकारी नौकरियों में एक तिहाई नौकरियाँ, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे सात फीसद कर दिया है।



## क्या है मांग

आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द कर सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए अधिकतम पांच फीसद आरक्षण जारी रखते हुए आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2018 में आरक्षण रद्द करने की अधिसूचना जारी होने से पहले तक सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा (स्वाधीनता सेनानी), जिलावार, महिला, अल्पसंख्यक और विकलांग इन पांच वर्गों में कुल 56 फीसद आरक्षण का प्रावधान था।

कोई भी सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा (स्वाधीनता सेनानी), जिलावार, महिला, अल्पसंख्यक और विकलांग इन पांच वर्गों में कुल 56 फीसद आरक्षण का प्रावधान था।

## जानें-समझें

## ट्रंप पर हमला

## अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की साख पर सवाल

## जन्सत्ता संवाद

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सिक्रेट सर्विस की आलोचना हो रही है। रिपब्लिकन नेता सुरक्षा एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी में से एक सिक्रेट सर्विस की साख पर उठते सवाल चिंता का विषय है। आइए जानते हैं क्या है सिक्रेट सर्विस और यह कैसे करती है काम।

सिक्रेट सर्विस के कंधों पर मौजूदा एवं पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति हमेशा सिक्रेट सर्विस के तेजतर्रार एवं काबिल एजेंटों के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। अमेरिका की यह सिक्रेट सर्विस गृह मंत्रालय के तहत आती है। राष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के अलावा, यह एजेंसी आपराधिक जांच एवं जाली मुद्रा और आर्थिक अपराधों की भी जांच करती है। साल 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकेन्ली की हत्या के बाद इस एजेंसी पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, उनके परिवार एवं अमेरिका पहुंचने वाले विदेशी नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई।

## कब हुई स्थापना

अमेरिका जब अपने गृह युद्ध के अंतिम दौर से गुजर रहा था तो उस समय अमेरिका में आधी करेंसी के जाली होने का अनुमान था। इसकी जांच के लिए 1865 में डिपार्टमेंट आफ ट्रेजरी के अधीन सिक्रेट सर्विस की स्थापना हुई। जाली नोटों पर बहुत हद तक रोक लगाने के बाद सिक्रेट सर्विस संघीय अपराधों एवं तस्करों जैसे अपराधों की जांच करती रही। आगे चलकर 1908 में जब फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) का गठन हुआ तो सिक्रेट सर्विस के जांच के दायरे को सीमित कर दिया गया। फिर भी साइबर क्राइम सहित बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर के अपराधों की जांच सिक्रेट सर्विस करती रही। कुछ समय बाद सिक्रेट सर्विस के सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए उसे राजनीति की दिग्गज हस्तियों एवं सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। एजेंसी



(फाइल फोटो)



क्या हुआ, यह कैसे हुआ और हम इस तरह की घटना को फिर से होने से कैसे रोक सकते हैं। हम सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं।

-किम्बली ए चौटल, सिक्रेट सर्विस प्रमुख

संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के साथ सिक्रेट सेवा यह समझने की कोशिश कर रही है कि

किसी भी खुले इलाके में हमले को रोकना बेहद कठिन है। जांच हमें यह पता करने का मौका देगी कि



आखिर गलती कहाँ हुई और भविष्य में क्या किया जा सकता है। हालांकि यह हमला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।  
- लॉफ्टिनर्न कर्नल जार्ज बिरेन्टा, पॉसिबिलिया राज्य पुलिस

को जिन राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। उनमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का परिवार, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष और चुनाव से 120 दिन पहले राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शामिल हैं।

## बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं

सिक्रेट सर्विस के सदस्य अपने साथ अत्याधुनिक हथियार लेकर चलते हैं। देश के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध के लिए वे बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मीडिया रपट की मानें तो सिक्रेट सर्विस में करीब 3,200 सदस्य काम करते हैं। इनमें से करीब 1,300 सक्रिय सदस्य हैं जबकि 2000 के करीब तकनीकी, पेशेवर और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं।

## कामकाज एफबीआई-सीआईए से अलग

सिक्रेट सर्विस का कामकाज एफबीआई से अलग है। संघीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया सूचनाओं

## जन्सत्ता संवाद

रूस के साथ भारत की नजदीकियाँ बढ़ने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा है। अब खबर है कि अमेरिका भारत को तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन की आपूर्ति में देरी कर रहा है। इसकी वजह से तेजस के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। स्मृतिकन की रपट के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ अनुबंध भी खत्म कर सकता है।

स्मृतिकन ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हवाले से लिखा, अगर वाशिंगटन भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए जेट इंजन की आपूर्ति में पिछड़ता रहा तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठ जाएगा। ऐसे में अनुबंध को भी समाप्त किया जा सकता



## विश्व परिक्रमा

## भारत और रूस की दोस्ती पर अमेरिका की नजर

## जन्सत्ता संवाद

रूस के साथ भारत की नजदीकियाँ बढ़ने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा है। अब खबर है कि अमेरिका भारत को तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन की आपूर्ति में देरी कर रहा है। इसकी वजह से तेजस के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। स्मृतिकन की रपट के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ अनुबंध भी खत्म कर सकता है।

स्मृतिकन ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हवाले से लिखा, अगर वाशिंगटन भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए जेट इंजन की आपूर्ति में पिछड़ता रहा तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठ जाएगा। ऐसे में अनुबंध को भी समाप्त किया जा सकता



है। एअर मार्शल (सेवानिवृत्त) एम माथेस्वरन ने कहा कि अमेरिकी एफ 404 इंजन की सप्लाई में देरी से भारतीय वायुसेना पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेजस एमके1 और तेजस एमके1ए के 6

स्क्वाड्रन इंजन ही सर्विस में शामिल किए जाने वाले हैं। माथेस्वरन ने कहा, भारतीय वायु सेना 45 की जगह 32 स्क्वाड्रन से काम चला रही है। अगर तेजस लड़ाकू विमान की अगली पीढ़ी के इंजन भारत को नहीं मिलते हैं तो अनुबंध खतरे में पड़ जाएगा। वहीं, मीडिया रपट से पता चलता है कि तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विमान के लिए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब तेजस योजना शुरू हुई थी, तब रूस कावेरी इंजन के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। वहीं, रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त पीके सहगल ने बताया कि भारत के लिए दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। 15 साल बाद क्या तकनीक अमेरिकी, यह भी देखना है। पांचवीं पीढ़ी के अलावा छठी पीढ़ी की तकनीक भी आ सकती है। ऐसे में भारत को भी तकनीक के मामलों में दूसरों से आगे रहना है।



## व्यक्तित्व

## ऐश्वर्य प्रताप : पेरिस ओलंपिक में सोने पर साधेंगे निशाना

## जन्सत्ता संवाद

ऐश्वर्य प्रताप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर अब पेरिस ओलंपिक में सोने पर निशाना साधेंगे। बचपन से ही निशानेबाजी के शौकीन तोमर को जब भी मौका मिलता था। तो वे पढ़ाई करने की बजाय पिता की शाटगन और ब्रेक-बैरल गन को साफ करते थे।

ऐश्वर्य को राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले ही वर्ष में तकनीकी कारणों से निलंबित कर दिया गया था। वह एक साल तक किसी भी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उनके मुताबिक यह उनके करिअर का सबसे कठिन दौर था। ऐश्वर्य मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले हैं। ऐश्वर्य का जन्म तीन फरवरी



2001 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रतनपुर गांव में राजपूत किसान परिवार में हुआ था। ऐश्वर्य के पिता को भी निशानेबाजी का शौक था ऐसे में उनके घर पर पहले से बंदूक मौजूद थी। उनके भाई एक पेशेवर निशानेबाज थे जिसे देखकर ऐश्वर्य ने भी स्कूल के समय से ही इसमें शानदार प्रदर्शन करने का लक्ष्य बना लिया था। 2015 में, ऐश्वर्य ने भोपाल में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में वैभव शर्मा के तहत निशानेबाजी में अपना पेशेवर प्रशिक्षण शुरू किया। भोपाल में प्रशिक्षण के दौरान उनकी लगन देखकर कोच ने उन्हें आगे बढ़ाना शुरू किया। चार साल के प्रशिक्षण

के बाद ऐश्वर्य ने 2019 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। इसके बाद साल 2020 लीगकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कोटा स्थान पाने में बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद ऐश्वर्य ने देश की राजधानी नई दिल्ली में 2021 में आयोजित विश्व कप प्रतियोगिता में 50 मीटर निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में भाग लेने से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद वे रुके नहीं। उन्होंने 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा और 50 मीटर एअर राइफल इवेंट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन किया। ये

उनके लिए काफी बड़ा पल था हालांकि वे टोक्यो में कोई मेडल नहीं ला पाए थे लेकिन अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐश्वर्य ने निशानेबाजी में कई कीर्तमान बनाए हैं। वे 2019 एशियाई एअरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल के कांस्य पदक विजेता थे। वे 2019 आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप के भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ऐश्वर्य ने 2023 में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। निशानेबाजी में उनकी उपलब्धियां को देखते हुए साल 2023 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में धिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी 2024’ से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू की और आइआइटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रपट पेश करेगी।

नीट-यूजी पर्चाफोड़ मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आइआइटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत

## प्रधानमंत्री खुद को लोकतांत्रिक साबित करें : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद के मानसूत्र सत्र के शुरु में विपक्ष को लेकर उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की, जबकि उन्होंने ‘10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज दबाई जिसकी सजा जनता ने हालिया लोकसभा चुनाव में उन्हें दी।’

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को ‘मोदी सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। खेड़ा ने एक बयान में कहा कि ‘जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज दबाई, वो आज प्रतिपक्ष के आवाज उठाने पर रुदन करना हुआ बेहद कमजोर दिख रहा था।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिपक्ष पर अशोभनीय टिप्पणी के साथ मानसूत्र सत्र की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को यह याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 साल के उनके अन्याय काल में पूरे देश का दम घोंटा गया, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी है। प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि वो बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं, दो दलों के सहयोग से चलने वाली राजग सरकार के एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ‘मोदी सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। उनका कहना था, ‘प्रधानमंत्री को स्मरण कराना उचित होगा कि जब वे ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त देश के 32 लाख विद्यार्थियों की आवाज को दबाने और उनके साथ आपकी सरकार के अन्याय के खिलाफ देश का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।’ खेड़ा ने कहा कि देश के 15 से अधिक अग्निवीर देश के लिए प्राणों की आहुति का सपना अपने दिल में रख कर आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके हैं।’ उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये भाषण दे रहे थे, तब देश के 50 करोड़ किसान अपने खेत और अपनी खेती को बचाने के लिए हर दमन, हर अत्याचार को सहते हुए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आपने ढाई साल से गला घोट रखा है।’

## पेज 1 का बाकी सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार है? इस प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आइसालसी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रही। चौधरी ने कहा कि फैसला उक्त सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा, ‘पूर्व में विशेष श्रेणी के दर्जे के बिहार के

## सवाल उठाकर विवादों में धिरीं वरिष्ठ अधिकारी

बताया। शिवसेना (उद्धव) नेता ने ‘एक्स’ पर कहा कि यह देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह किस तरह से अपनी सीमित सोच और विशेषाधिकार दिखा रहे हैं।सभरवाल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ‘नेशनल प्लेटफार्म फार द राइट्स आफ द डिसेबल्ड’ (एनपीआरडी) की तेलंगाना इकाई ने कहा कि तेलंगाना सरकार को आइएमए (एनडीसी) पोस्ट के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह दिव्यांगों का अपमान है।

एनपीआरडी, तेलंगाना के अध्यक्ष के वेंकट ने केंद्रीय सेवाओं में दिव्यांगों के लिए कोटा लागू करने के पक्ष में अदालती फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सभरवाल की पोस्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के समानता के मार्गदर्शक सिद्धांत के खिलाफ है।



चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि आइआइटी दिल्ली के निदेशक तीन विशेषज्ञों की एक समिति का तत्काल गठन करें। यह समिति प्रवेश परीक्षा में आए एक सवाल

## मोदी ने विपक्ष पर ‘नकारात्मक राजनीति’ करने का आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री का गला घोटने, आवाज दबाने का प्रयास हुआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर ‘नकारात्मक राजनीति’ करने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद का ‘दुरुपयोग’ करने का आरोप लगाया तथा कहा कि संसद किसी ‘दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है।’संसद सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने ढाई घंटे तक देश के ‘प्रधानमंत्री का गला घोटने’ का प्रयास किया। मोदी ने कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला दे दिया है और अब सभी राजनीतिक दलों को अगले पांच साल देश के लिए मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने यह अपील सभी दलों के सांसदों से की। उन्होंने हाल में संपन्न आम चुनाव की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘गत जनवरी से लेकर (जून में आम चुनाव संपन्न होने तक) हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, जितनी लड़ाई लड़नी थी…

## सद्भाव व सुरक्षा के बीच निकली ब्रज मंडल यात्रा मुसलिम समूहों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया, इंटरनेट सेवा बहाल

चंडीगढ़, 22 जुलाई (भाषा)।

पिछले साल हिंसा से प्रभावित रही ब्रज मंडल जलाधिपेक यात्रा सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। यात्रा संपन्न होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। हिंद-मुसलिम दोनों समुदायों के लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर शोभायात्रा का स्वागत किया। आध्यात्मिक नेता महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि इस साल की यात्रा ने पूरे देश में भाईचारे का मजबूत संदेश दिया है। ‘हर हर महादेव’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए भक्तों ने नरहड़ महादेव मंदिर से यात्रा शुरू की और बाद में यहां फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर के लिए रवाना हुए। नूंह के उपयुक्त

## पेज 1 का बाकी सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आइएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आइएमजी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।’
वर्ष 2012 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार केंद्र में थी। राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग सोमवार को राज्यसभा में भी उठी। राजद के सदस्य मनोज झा ने उच्च सदन में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ-साथ विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। राजद सदस्य ने जद (एकी) की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कहते हैं कि विशेष राज्य न दे सको तो विशेष पैकेज पैकेज दो। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में ‘या’ नहीं है। बिहार को ‘या’ स्वीकार नहीं है।

अपनी पोस्ट के लिए हुई आलोचना के मद्देनजर सभरवाल ने सोमवार को दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस बात की भी पड़ताल करें कि आइपीएस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया है और आइएएस भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी टाइमलाइन पर काफी आक्रोश देखने को मिला है।

दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे इस बात की भी जांच करें कि यह कोटा अभी तक आइपीएस, आइएफओएस और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा सीमित तर्क यह है कि आइएएस भी इससे अलग नहीं है। सभरवाल ने ‘एक्स’ पर चतुर्वेदी और अन्य की टिप्पणियों का भी जवाब दिया है।

*सुप्रीम* कोर्ट की पीठ ने आइआइटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रपट पेश करेगी। पीठ विवादों से धिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

के सही जवाब पर राय दे। दरअसल, एक ऐसे सवाल का मसला उठा है, जिसके दो सही उत्तर माने जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने विशेषज्ञों की एक समिति से ही इस पर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि भौतिक



*बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना*
लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयों पर आठ घंटे की चर्चा और चार मंत्रालयों के कामकाज पर चार-चार घंटे की बहस होने की संभावना है। केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी- बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन अब वो ( चुनाव प्रचार का) दौर समाप्त हुआ है, देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया है।’

उन्होंने कहा, ‘अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेदारी है कि…आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जुड़ना है। एक और नेक बनकर जुड़ना है।’ प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से ऊपर उठने और अगले चार से साढ़े चार वर्षों तक संसद के मंच का उपयोग करने का आ’"न किया।



उन्होंने कहा, ‘जनवरी 2029 चुनाव का वर्ष होगा। आप उसके बाद जाइए मैदान में। सदन का भी उपयोग करना है, कर लीजिए। वह (आम चुनाव से पहले के) छह महीने, जो छह खेलने हैं, खेल लीजिए। लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश, देश के गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जनभागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं।’ मोदी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद कोई सांसद पांच वर्ष के लिए आया और कुछ को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत

## संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

तथा ज्यादा ‘रिटर्न’ की उम्मीदों के कारण सट्टेबाजी की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित करता है और सरकार द्वारा लागू गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी प्रदर्शित करता है।समीक्षा में कहा गया है कि देश का वित्तीय क्षेत्र तेजी के रास्ते पर है। कर्ज के लिए बैंक पर निर्भरता कम हो रही है और पूंजी बाजार की भूमिका बढ़ रही है।

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित और स्वागतयोग्य है। इसमें काम गया है कि हालांकि, पूंजी बाजार पर निर्भरता और उसके उपयोग की अपनी चुनौतियों भी हैं। ऐसे समय जब, भारत का वित्तीय क्षेत्र इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, उसे

## नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

सुधार के लिए क्या कदम उठा कर रही है? बाद में संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी ने वह ‘नीट-यूजी’ में कथित अनियमितता का मुद्दा संसद के भीतर उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है।इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें किसी से बौद्धिकता और संस्कार का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। देश के लोकतंत्र ने हमारे प्रधानमंत्री को चुना है, वह उनके निर्णय से हटने जवाब दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सदन में देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहा गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण निदनीय कुछ नहीं हो सकता। प्रधान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई हैं, उनके समय के शिक्षा मंत्री 2010 में तीन विधेयक लेकर आए थे, उनमें एक विधेयक शिक्षा में सुधार से जुड़ा था। यह मौजूद सरकार की हिम्मत है कि पर्चाफोड़ पर कानून बनाया गया, लेकिन कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष की क्या मजबूरी थी कि उनके समय लाए गए विधेयक को वापस लिया गया? क्या निजी मेडिकल कालेज और उनकी घूसखोरी के दबाव में इसे वापस लिया गया था? धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि नीट से जुड़े

विज्ञान के दो सही विकल्पों वाले सवाल नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। दो सही विकल्प देने से 44 परीक्षार्थियों को बोनस अंक मिले और 4.2 लाख परीक्षार्थियों को नुकसान हुआ है। लिहाज विशेषज्ञों की राय लिया जाना जरूरी है। नीट-यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई आइआइटी के निदेशक को निर्देश के साथ ही खत्म हो गई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई 23 जुलाई यानि मंगलवार को होगी। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र दिया गया था। इन्हें एक्सबीआइ की जगह केनरा बैंक का प्रश्न पत्र बांटा गया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पर्चाफोड़ (4 मई) की रात को हुआ है तो जाहिर है कि लोक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्टॉफ रूम से पहले हुआ था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि 4,20,774 उम्मीदवारों ने विकल्प दो (पुराने एनसीईआरटी संस्करण का उत्तर) और 9,28,379 उम्मीदवारों ने विकल्प चार का प्रयास किया।एसजी ने कहा कि एनटीए ने परीक्षार्थियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद विकल्प दो के लिए अंक देने का निर्णय लिया, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई-बहनों की पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया था।



से सांसद ऐसे थे, जिनको अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवरस ही नहीं मिला। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा, ‘क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश को संसद के अहम समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढंकने के लिए दुरुपयोग किया है।’ प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि कम से कम पहली बार सदन में पहुंचने वाले सदस्यों को अवरस और चर्चा के दौरान अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि उस दौरान 140 करोड़ देशवासियों की आवाज को कुचलने का ‘अलोकतांत्रिक’ प्रयास हुआ था। उन्होंने पिछले सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर लोकसभा में उनके जवाब के दौरान विपक्ष के लगातार हंगामे की ओर संकेत करते हुए कहा कि ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का… लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पर्चाफोड़ (4 मई) की रात को हुआ है तो जाहिर है कि लोक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्टॉफ रूम से पहले हुआ था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि 4,20,774 उम्मीदवारों ने विकल्प दो (पुराने एनसीईआरटी संस्करण का उत्तर) और 9,28,379 उम्मीदवारों ने विकल्प चार का प्रयास किया।एसजी ने कहा कि एनटीए ने परीक्षार्थियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद विकल्प दो के लिए अंक देने का निर्णय लिया, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई-बहनों की पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया था।

## राजौरी में सैन्य चौकी पर आतंकी हमले की कोशिश नाकाम

राजौरी, 22 जुलाई (भाषा)।
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के जवानों ने एक सैन्य चौकी और ग्राम रक्षा दल सदस्य के आवास पर आतंकवादी हमले की कोशिश सोमवार तड़के नाकाम कर दी। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि घटना में सलिस आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया और इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। वीडोजी के आवास पर हमला करने में शामिल आतंकवादी को मार गिराया गया है और इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडोजी का रिश्तेदार घायल हुआ है। वाइट नाइट कोर ने ‘एक्स’ पर बताया कि राजौरी के गुंथा इलाके में आतंकवादियों ने वीडोजी के घर पर तड़के तीन बजकर 10 मिनट पर हमला किया। नजदीक मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।‘अभियान अब भी जारी है।’ इसमें बताया गया कि भारतीय सेना ने राजौरी-रियासी के दूरदराज के इलाके में स्थित वीडोजी के गांव पर संभावित हमले के खतरे को लेकर आई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की।

रणनीतिक टीम ने तत्काल कार्रवाई की, ताकि वीडोजी सदस्य और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हो। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने वीडोजी और पूर्व सैनिक परपोषित कुमार के खवास तहसील के गुंथा इलाके स्थित आवास पर गोलीबारी की। कुमार शौर्य चक्र से भी सम्मानित हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंकने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने सुबह करीब चार बजे क्षेत्र में नव स्थापित सेना चौकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने सेना की चौकी पर किए गए हमलों को नाकाम कर दिया और इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।



सोमवार को नूंह के नलहर महादेव मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रज मंडल जलाधिपेक यात्रा करते साधु।

## संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

फ्रीसद है। यानी इसमें आगे सुधार की काफी गुंजाइश है।संसद में पेश समीक्षा में अप्रैल में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 6.5 फीसद से 7.0 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।

यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की 8.2 फीसद की वृद्धि की तुलना में कम है। साथ ही यह चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआइ के 7.2 फीसद अनुमान से भी कम है। समीक्षा की प्रस्तावना में लिखा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रही है।’ हालांकि, इसमें यह भी कहा कि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सरते आयात की आशंका निजी पूंजी के निर्माण को सीमित कर सकती है। समीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि इस वर्ष के लिए वृद्धि दर का

अनुमान जताते समय सतर्कता बरती गई है और यह बाजार की अपेक्षाओं से कम है। इस सतर्क रुख का कारण निजी क्षेत्र के निवेश की गति धीमी होने के साथ ही मौसम प्रतिक्रम का अनिश्चित होना है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि में यदि संरचनात्मक सुधार लागू किए गए तो टिकाऊ आधार पर सात फीसद से अधिक की वृद्धि दर की संभावना बनती है।

समीक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने, छोटी कंपनियों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने, छोटी कंपनियों के लिए कारोबार को सुगम बनाने और आय असमानता पर गौर करने की भी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिकताओं में शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटना भी शामिल होना चाहिए।

उन्होंने कटाक्ष किया कि यह सरकार पर्चाफोड़ का कीर्तिमान बनाएगी। साथ ही सवाल किया कि क्या सरकार उन छात्रों की सूची जारी करेगी, जिनके सबसे ज्यादा अंक आए हैं। क्योंकि, कुछ परीक्षा केंद्रों पर दो हजार से ज्यादा बच्चे उतीर्ण हो गए हैं। इस पर धर्मेद्र प्रधान ने पलटवार किया और कहा कि वे इस सदन में उन पर्चाफोड़ मामलों की पूरी सूची रख सकते हैं, जो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए थे। इसके बाद प्रधान ने सोशल मीडिया मंच एसएलए एंवां बेटे है कि विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल नहीं उठें। इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करें कि परीक्षा पर सवाल नहीं उठे और इस पर एक सुझाव दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार भी उत्तम सुझाव को मानेगी। अगर हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो उतीर्ण होने वाले बच्चों के भविष्य व देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर होगा, जो सदन के लिए चिंता का विषय है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ( नीट) में कथित अनियमितता को लेकर सदन में दावा किया कि धर्मेद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में 70 पर्चाफोड़ के मामले सामने आए हैं। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें रही हैं, जहां परीक्षाओं पर प्रश्न उठे, हम इसलिए एंवां बेटे है कि विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल नहीं उठें। इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करें कि परीक्षा पर सवाल नहीं उठे और इस पर एक सुझाव दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार भी उत्तम सुझाव को मानेगी। अगर हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो उतीर्ण होने

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के जवानों ने एक सैन्य चौकी और ग्राम रक्षा दल सदस्य के आवास पर आतंकवादी हमले की कोशिश सोमवार तड़के नाकाम कर दी। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि घटना में सलिस आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया और इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। वीडोजी के आवास पर हमला करने में शामिल आतंकवादी को मार गिराया गया है और इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडोजी का रिश्तेदार घायल हुआ है। वाइट नाइट कोर ने ‘एक्स’ पर बताया कि राजौरी के गुंथा इलाके में आतंकवादियों ने वीडोजी के घर पर तड़के तीन बजकर 10 मिनट पर हमला किया। नजदीक मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।‘अभियान अब भी जारी है।’ इसमें बताया गया कि भारतीय सेना ने राजौरी-रियासी के दूरदराज के इलाके में स्थित वीडोजी के गांव पर संभावित हमले के खतरे को लेकर आई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की।

अधिकारियों ने बताया कि घटना में सलिस आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया और इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। वीडोजी के आवास पर हमला करने में शामिल आतंकवादी को मार गिराया गया है और इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडोजी का रिश्तेदार घायल हुआ है। वाइट नाइट कोर ने ‘एक्स’ पर बताया कि राजौरी के गुंथा इलाके में आतंकवादियों ने वीडोजी के घर पर तड़के तीन बजकर 10 मिनट पर हमला किया। नजदीक मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।‘अभियान अब भी जारी है।’ इसमें बताया गया कि भारतीय सेना ने राजौरी-रियासी के दूरदराज के इलाके में स्थित वीडोजी के गांव पर संभावित हमले के खतरे को लेकर आई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की।

रणनीतिक टीम ने तत्काल कार्रवाई की, ताकि वीडोजी सदस्य और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हो। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने वीडोजी और पूर्व सैनिक परपोषित कुमार के खवास तहसील के गुंथा इलाके स्थित आवास पर गोलीबारी की। कुमार शौर्य चक्र से भी सम्मानित हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंकने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने सुबह करीब चार बजे क्षेत्र में नव स्थापित सेना चौकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने सेना की चौकी पर किए गए हमलों को नाकाम कर दिया और इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।



सोमवार को नूंह के नलहर महादेव मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रज मंडल जलाधिपेक यात्रा करते साधु।

## संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

फ्रीसद है। यानी इसमें आगे सुधार की काफी गुंजाइश है।संसद में पेश समीक्षा में अप्रैल में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 6.5 फीसद से 7.0 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।

यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की 8.2 फीसद की वृद्धि की तुलना में कम है। साथ ही यह चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआइ के 7.2 फीसद अनुमान से भी कम है। समीक्षा की प्रस्तावना में लिखा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रही है।’ हालांकि, इसमें यह भी कहा कि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सरते आयात की आशंका निजी पूंजी के निर्माण को सीमित कर सकती है। समीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि इस वर्ष के लिए वृद्धि दर का

## नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें

की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने कहा कि राज्य के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक है, लेकिन इसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है। सिंघवी को अतिशयोक्ति से बचने के लिए कहते हुए पीठ ने कहा कि इन आदेशों से सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी जुड़े हैं।

सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से जारी है और विभिन्न धार्मिक आस्थाओं-इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किए गए हैं। पीठ ने पूछा कि वे (कांवड़िए) शिव की पूजा करते हैं, हां? क्या वे उम्मीद करते हैं कि भोजन निश्चित समुदाय द्वारा पकाया, परीसा और पैदा किया जाएगा? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। मोड़ना ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे निर्देश समुदायों के बीच विवाद को बढ़ावा देते हैं।

## प्ररूप संख्या आईएनसी -26

[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार ]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई शक्ति) उत्तरी क्षेत्र के संघ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और मनु महाराणी होटल्स लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्सीओ-310, तीसरी मंजिल, सेक्टर-29, मुडगांव-122001, हरियाणा में स्थित है, के मामले में,

.....याधिकारकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के संसद कर्तवी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए 16 मई, 2024 को आवेदन असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संसद ज्ञान में संचालन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिवाय प्ररूप फाइल कर एम्सीओ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता या एक साथ पत्र जिसमें उनके हित का संक्षेप और उससे विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पता: बी-2, विंग हार्दित, वन, चण्डीगढ़ नगर, सीओओ ऑफिस, नई दिल्ली - 110 003, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। या सुर्द कर सकते हैं और स्वकीय प्रति आवेदन करती है।

मनु महाराणी होटल्स लिमिटेड  
सीआईएन: U55101HR1988PLC057155  
सीएसओ नंबर: 310, तृतीय तल, सेक्टर-29, मुडगांव-122001, हरियाणा, ईमेल आईडी: companysecretary@dsigroup.com

मनु महाराणी होटल्स लिमिटेड की ओर से

हस्ता/—  
अतुल जैन  
सीआईएन-00060933  
निदेशक

तारीख: 22.07.2024, स्थान: मुडगांव

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income	10.78	15.10	18.13	53.30
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax))	5.09	10.16	(1.98)	19.81
6	Paid up equity share capital (Face value of Rs. 1 each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year				(691.27)
8	Earnings per share (Face value of Re. 1 each) (Basic and Diluted) (In Rs.)	0.001	0.006	(0.007)	0.002

**JAI MATA GLASS LIMITED**  
CIN: L26101HP1981PLC004430, Regd. Office: TIPRA, BAROTWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103  
Statement of Audited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2024 (Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income	10.78	15.10	18.13	53.30
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax))	5.09	10.16	(1.98)	19.81
6	Paid up equity share capital (Face value of Rs. 1 each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year				(691.27)
8	Earnings per share (Face value of Re. 1 each) (Basic and Diluted) (In Rs.)	0.001	0.006	(0.007)	0.002

**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कंपनी लिमिटेड**  
कोर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रैटर, सी 54-55, सुपर बी-4, थिरु-नि-का इन्डियन एस्टेट, मिडी, चेन्नई-600 001, चंडीगढ़ शाखा: एस्सीओ 350-351-352, तीसरी मंजिल, सेक्टर-29-ए, चंडीगढ़-160022, चण्डीगढ़ शाखा: एस्सीओ 105, सेक्टर 17, एस्सीओ कार्पोरेट बिल्डिंग बेट, पेद्रोला पते के पास, कोर्ट रोड, जगधरी, यमुनानगर 135003, संपर्क: श्री चंद्र मोहन सिंह रावत मोबाइल नंबर 895045100 और श्री वरुण प्रताप वोहरा मोबाइल नंबर 9065655002

सूचना (बिना किसी पूर्ववह के)

1. अनिल ब्रु, 2. दीपि ब्रु, 3. अनिल ब्रु सरकारी केन्द्रीय समी निवासी: मकान नं. 21, कृष्णा कॉलोनी, नारंग अकौरी के सामने, यमुना नगर-135001, थिय महोदय/महोदया, यह निमानुसार प्रस्तुत है।

1. मुझे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कंपनी लिमिटेड के लिए सरकारी अधिनियम, 2002 के तहत बनाया गए सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका शाखा कार्यालय चंडीगढ़ में एस्सीओ. 350-351-352, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़ में है और शाखा कार्यालय एस्सीओ. 105, प्रथम तल सेक्टर 17, एस्सीओ कार्पोरेट बिल्डिंग बेट, पेद्रोला पते के पास, कोर्ट रोड, जगधरी, यमुनानगर में है।

2. यह कि सुरक्षित परिसंपत्ति का मौलिक कथन दिनांक 05.07.2024 को लिया गया है और जिसकी सूचना आपको भविष्य में दी गई है, जिसमें कबो के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले परिसर खाली करने का अनुरोध किया गया है। यह कि आपको उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता सहित ई-नीलामी बिक्री नोटिस दिनांक 11-07-2024 के बारे में पंजीकृत डाक और प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया से दी गई है, जिसके अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति की नीलामी की तारीख सरकारी अधिनियम के नियमों के अनुसार 31.07.2024 के लिए तय की जा रही है।

3. सरकारी अधिनियम के नियमों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को खाली करने के कई अनुरोधों के बाद भी, पर के कुछ सामान अभी भी सुरक्षित संपत्ति के परिसर में है, विधिवत हस्ताक्षरित सूची भी तदनुसार तैयार की गई है। आपसे अनुरोध है कि नोटिस प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर तैयार और भविष्य हस्ताक्षरित सूची के अनुसार अपने सभी सामान और खरूंद हटा दें क्योंकि उस तारीख तक CIFCL पर न रहे सामान और वस्तुओं को संश्लिष्ट करने के लिए सभी खर्च वहन कर रहा है। इन नोटिस को आपको सामान और वस्तुओं को हटाने का अंतिम और अंतिम अवसर माना जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि आप मुझे (सीआईएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी) कांच दिवसों में कार्यालय दिनों के दौरान मिलकर कार्यक्रम तय करें।

दिनांक: 23/07/2024  
स्थान: चंडीगढ़/यमुना नगर

प्राधिकृत अधिकारी- मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कंपनी लिमिटेड

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
एच. आर्यावर्त: 11वीं मंजिल, टावर ए, वीनिसिया रिजिडेंस पार्क, मंगलपूर टाटा कम्पन, नई दिल्ली, मुम्बई-400013 सीआईएन नंबर U67190MH2008PLC187552

कच्चा सूचना (असह संपत्ति के लिए)

(सूचना हित प्रवर्तन विवरण, 2002 के विवरण 8(1) के साथ संश्लिष्ट परिशिष्ट IV के अनुसार)

जहाँकि, वित्तीय संपत्तियों का प्रतिनिधिकरण और पुनर्निर्माण और सूचना हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोगस्तरीय टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, में नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित शर्तों का भुगतान करने के लिये कहा गया था।

उधारकर्ता, जहाँकि सूचना में विवरण देने पर, उधारकर्ता को, विशेष रूप से और जगता को, सामान्य रूप से संचालित किया जाता है, कि नीचे वर्णित संपत्ति पर अधोस्तरीय में धारा 13(4) उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जगता को संचालित की जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बलुके जिसमें ब्याज सहित नीचे दी गई शर्त शामिल होगी। उस पर और नीचे उल्लिखित शर्तों से बंधनकारी ब्याज, बुरुक, लागत आदि के अधीन होना।

सुरक्षित संपत्तियों को भुगतान के लिए चरमकृत मांग के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	सूचना	वित्तीय संपत्तियों/कानूनी उधारकर्ताओं/कानूनी प्रतिनिधि (ओ) का नाम	दिनांक नोटिस की शर्त और तिथि	कच्चा की तिथि
TCHN03	137899	सम्पूर्ण श्री राम जी वर्मा पूर्व श्री बन्धु वर्मा अपने कानूनी उधारकर्ता (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती शक्ति वर्मा पत्नी सम्पूर्ण श्री राम जी वर्मा (सह-उधारकर्ता) और कानूनी उधारकर्ता के रूप में) और शक्ति वर्मा अपने कानूनी उधारकर्ता के रूप में) और श्री शक्ति वर्मा पूर्व स्वर्णि श्री राम जी वर्मा (कानूनी उधारकर्ता के रूप में) के माध्यम से	29/07/2024 18-07-2024 तक ₹. 7,97,412/- (सात लाख नब्बे हजार चार सौ बाइस रुपये मात्र)	18-07-2024

सुरक्षित संपत्तियों/असह संपत्तियों का विवरण- 69.75 वर्ग मीटर के प्लॉट पर आवासीय पर 10/11 का बस स्टॉप टुकड़ा और पार्किंग (80'x15'), मोटा चलोटी, मोल्डला देव नगर, शाहर मिरोजाबाद, गिला मिरोजाबाद - 283202 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, मिडी कोर्ट में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं: पूर्व सोहन लाल, पश्चिम आनंद स्वयं, उत्तर रोड, दक्षिण प्लॉट

दिनांक: 23/07/2024  
स्थान- विक्रोलाबाद (उत्तर प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

www.readwhere.com

www.read

## खबर कोना

## आइएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने के बाद नाविक लापता

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

मुंबई पोतगाह में नौसेना के बहुउद्देशीय युद्धपोत 'आइएनएस ब्रह्मपुत्र' में आग लगने के बाद एक नाविक लापता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय युद्धपोत 'आइएनएस ब्रह्मपुत्र' में 21 जुलाई की शाम उस समय आग लग गई थी, जब नौसेना के मुंबई स्थित पोतगाह में उसकी मरम्मत की जा रही थी। इसमें कहा गया, 'जहाज के चालक दल ने अग्निशमनकर्मियों की मदद से 22 जुलाई सुबह तक आग पर काबू पा लिया।' बयान में कहा गया कि सोमवार को दोपहर जहाज एक ओर झुक गया। इसमें कहा गया, 'तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा नहीं किया जा सका।

## पद्म पुरस्कार के लिए 15 सितंबर तक नामांकन

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2025 के लिए नामांकन की आंतिम तारीख 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आनलाइन किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल हैं, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

## दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को मस्कट भेजा गया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

अबु धाबी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ रहे इंडिगो के एक विमान को सोमवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण मस्कट की ओर मोड़ दिया गया। एयरलाइन ने बयान में कहा कि आवश्यक रखरखाव के बाद विमान पुनः परिचालन में आ जाएगा। विमान में यात्रियों की संख्या के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है। बयान के अनुसार, 'अबु धाबी से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6ई 1406 को तकनीकी खराबी के कारण मस्कट की ओर मोड़ दिया गया।' बयान में कहा गया है कि यात्रियों को मस्कट में होटल में ठहराने की प्रेरणाश की गई है। उड़ानों की निगरानी रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरेडार 24 के अनुसार, यह उड़ान ए320 नियो विमान संचालित कर रहा था। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों के गंतव्य तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

## 'पीएम-सूर्य घर योजना के तहत 4,950 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत डिस्काम को 4,950 करोड़ रूप्य का प्रोत्साहन देने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि डिस्काम को प्रोत्साहन देने के माध्यम से बरेलाइन स्तर के अलावा अतिरिक्त ग्रिड की स्थापना - जुड़ी हुई रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है। उन्होंने कहा, 'पीएम सूर्यघर के तहत डिस्कॉम को 4,950 करोड़ रूप्य का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के प्रभावी वितरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।' एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिस्काम (बिजली वितरण कंपनियां) को प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश पिछले सप्ताह 18 जुलाई को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अधिसूचित किए थे।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सोमवार को बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा में भारत के कृषि क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता बताई गई। समीक्षा में चेतावनी दी गई कि संरचनात्मक मुद्दे देश की समग्र आर्थिक वृद्धि की राह में बाधा बन सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत समीक्षा में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय कृषि क्षेत्र की गैर-प्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कृषि क्षेत्र पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का आ'न किया। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत ने अभी तक आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अपने कृषि क्षेत्र का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है, जैसा कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और पश्चिमी विकसित देशों ने किया है। समीक्षा में कहा गया है, 'भारतीय कृषि अभी संकट में नहीं है, लेकिन इसमें गंभीर संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और जल संकट का खतरा मंडरा रहा है।'

## सीईए ने किसानों के लिए मौजूदा सरकारी सब्सिडी और सहायता उपायों के बावजूद मौजूदा नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत की।

सीईए ने किसानों के लिए मौजूदा सरकारी सब्सिडी और सहायता उपायों के बावजूद मौजूदा नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत की। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना में नागेश्वरन ने कहा, 'अगर हम कृषि क्षेत्र की नीतियों में बाधा डालने वाली गंठों को खोल दें तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।' उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पानी, बिजली और उर्वरकों पर सब्सिडी के साथ-साथ आयकर छूट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान करती है, लेकिन नीति कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश है। समीक्षा में कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है। इनमें खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन के साथ वृद्धि को संतुलित करना, मूल्य खोज में सुधार करना और भूमि विखंडन से निपटना शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समीक्षा में बहुआयामी सुधारों की सिफारिश की गई है, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, विपणन के अवसरों को बढ़ाना, खेती के नवाचारों को अपनाना, बर्बादी को कम करना और कृषि-उद्योग संबंधों में सुधार करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। समीक्षा ने सरकार को ध्यान बुनियादी खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि 'मांग-संचालित खाद्य प्रणाली' के साथ तालमेल में हो और जो पौष्टिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ दोनों हो।

समीक्षा में सुझाव दिया गया कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को



## सात फीसद वृद्धि दर का अनुमान मानसून पर निर्भर : नागेश्वरन

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए सात फीसद तक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने योग्य है। हालांकि, यह मानसून और वैश्विक स्तर पर वित्तीय जोखिम पर निर्भर करेगा। आर्थिक समीक्षा में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7.0 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। यह बीते वित्त वर्ष के 8.2 फीसद की वृद्धि दर से कम है।

नागेश्वरन ने कहा, 'हम निराशावादी नहीं हैं। वास्तव में हम आशावादी हैं। हम मानसून की प्रगति के संदर्भ में चुनौतियों को लेकर भी सतर्क हैं।' संसद में 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद नागेश्वरन ने संवाददाताओं से कहा कि हमने सोच-विचार कर 6.5 से 7.0 फीसद की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान रखा है और इसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि मानसूनी बारिश कैसी होती है। आर्थिक समीक्षा नागेश्वरन के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार की है। कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि समीक्षा में वृद्धि के अनुमान को कम करके दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि हम वृद्धि दर का अनुमान लगाने को लेकर सतर्क रुख रखना चाहते हैं।

स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 'इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।'

समीक्षा ने किसानों के हित में बाजारों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किसान-अनुकूल नीति ढांचे की आवश्यकता पर भी

नई दिल्ली

## आर्थिक समीक्षा में कृषिक्षेत्र के विकास पर जोर

## भारतीय कृषि अभी संकट में नहीं, सुधार की आवश्यकता

देश में 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियों का सृजन करने की जरूरत देश में बढ़ते कार्यबल को देखते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है।

समीक्षा में नौकरियों की संख्या का एक व्यापक अनुमान दिया गया है। बढ़ते कार्यबल के लिए इन नौकरियों को देश में सृजित करने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि नौकरियों से ज्यादा आजीविका पैदा करने के बारे में है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है।

## कृत्रिम मेधा के कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर अनिश्चितता

कृत्रिम मेधा (एआई) का विभिन्न कौशल वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी अनिश्चितता है। समीक्षा में यह अनुमान जताया गया है कि नए जमाने की प्रौद्योगिकी से उत्पादकता में तो वृद्धि होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कृत्रिम मेधा (एआई) 'नवोन्मेष' की तीव्र गति और उसके प्रसार में सुगमता के मामले में बेजोड़ है। लेकिन इससे आने वाले समय में काम के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत इस बदलाव से अछूता नहीं रहेगा।

## महिलाओं के लिए बजट आबंटन में लगातार हो रहा इजाफा

महिलाओं के बजट में लगातार वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2013-14 के 97,134 करोड़ रूप्य से बढ़कर 2024-25 में 3.1 लाख करोड़ रूप्य पर पहुंच गया है। इस तरह लैंगिंग बजट में इस साल 2023-24 की तुलना में 38.7

फीसद और वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 218.8 फीसद की वृद्धि हुई। यह राशि कुल केंद्रीय बजट का 6.5 फीसद है। समीक्षा में विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विषयी हस्तक्षेप और प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता ने महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी गई।

जोर दिया। आर्थिक समीक्षा ने कीमतों में उछाल के पहले संकेत पर वायदा या विकल्प (डेरिवेटिव) बाजारों पर प्रतिबंध लगाने से बचने की सिफारिश की।

वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा ने निरंतर रोजगार सृजन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन,

डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण) की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने कहा, 'वर्ष 2047 या उससे अधिक समय तक लगभग एक पीढ़ी तक वृद्धि को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है, नीचे से ऊपर की ओर सुधार आवश्यक है।'

## आर्थिक समीक्षा में गुलाबी तस्वीर पेश करने का प्रयास हुआ : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पेश आर्थिक समीक्षा में 'सब ठीक है' वाली गुलाबी तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया है, जबकि देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि मंगलवार को पेश होने वाला बजट देश की वास्तविकताओं के अनुरूप होगा। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि मंगलवाला को पेश होने वाले बजट से पहले जारी किया गया, एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के 'स्पिन डाक्टर्स' को कड़ी मशकत करनी पड़ी होगी। इसमें अर्थव्यवस्था की 'सब ठीक है' वाली गुलाबी तस्वीर पेश करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आर्थिक स्थिति इतनी निराशाजनक है।

उन्होंने दावा किया कि खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित बनी हुई है, जो प्रति वर्ष लगभग 10 फीसद पर है। कोरोना के बाद आर्थिक सुधार बेहद असमान रहा है। ग्रामीण भारत पीछे छूट गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में राजग सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का बखाना है। बिना तैयारी के और अनुचित ढंग से लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों एवं सरसे आयात में बेतहाशा वृद्धि के साथ आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग, किसानों की आय को कमजोर करने के लिए चिह्नित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार नीति की विफलता ने भी भारत की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करने में योगदान दिया है।

उन्होंने दावा किया कि खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित बनी हुई है, जो प्रति वर्ष लगभग 10 फीसद पर है। कोरोना के बाद आर्थिक सुधार बेहद असमान रहा है। ग्रामीण भारत पीछे छूट गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में राजग सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का बखाना है। बिना तैयारी के और अनुचित ढंग से लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों एवं सरसे आयात में बेतहाशा वृद्धि के साथ आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग, किसानों की आय को कमजोर करने के लिए चिह्नित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार नीति की विफलता ने भी भारत की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करने में योगदान दिया है। 2014 के बाद से, चीन से आयात का डीलग कुल आयात के 11 फीसद से बढ़कर 16 फीसद हो गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में राजग सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का बखाना है। बिना तैयारी के और अनुचित ढंग से लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों एवं सरसे आयात में बेतहाशा वृद्धि के साथ आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग, किसानों की आय को कमजोर करने के लिए चिह्नित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार नीति की विफलता ने भी भारत की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करने में योगदान दिया है। 2014 के बाद से, चीन से आयात का डीलग कुल आयात के 11 फीसद से बढ़कर 16 फीसद हो गया है।

## 'बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा होनी चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि इस बजट देश की वास्तविकताओं के सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की घोषणा करने की जरूरत है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से आग्रह किया कि किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमताहीनता व दुर्भावना से भरा व्यवहार सबसे अधिक हानिकारक है। उन्होंने दावा किया कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने गेहूं की एमएसपी 119 फीसद और धान की एमएसपी 134 फीसद बढ़ाया था, वहीं राजग सरकार ने इसे क्रमशः 47 फीसद और 50 फीसद बढ़ाया है। यह महंगाई और कृषि लागत की बढ़ती कीमतों के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

रमेश ने कहा कि किसानों का कर्ज बहुत बढ़ गया है। एनएसएसओ के अनुसार, 2013 के बाद से बकाया ऋण में 58 फीसद की वृद्धि हुई है। आधे से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हैं।

## 'महंगाई पर गौर करना बंद करे आरबीआइ'

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए और सरकार को गरीबों पर खाने के सामान की ऊंची कीमतों का असर कम करने को उन्हें 'कूपन' देने या सीधे नकदी हस्तांतरण पर विचार करना चाहिए। आर्थिक समीक्षा रपट में यह बात कही गई है।

हाल के महीनों में महंगाई दर में कमी आई है। लेकिन आरबीआइ ने बढ़ी हुई खाद्य महंगाई के हवाला देते हुए नीतिगत दर में कटौती से परहेज किया है। आरबीआइ की नीतिगत दर के आधार पर ही बैंक आवास, व्यक्तिगत और कंपनी ऋण की ब्याज तय करते हैं। भारत ने 2016 में महंगा लक्ष्य निर्धारण को लेकर रूपरेखा पेश की थी। इसके तहत रिजर्व बैंक

## बजट के एक दिन पहले सूचकांक, निफ्टी गिरावट के साथ बंद

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

आम बजट पेश होने से एक दिन पहले सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव से स्थानीय शेयर बाजार के मानक सूचकांक और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख ने भी निवेशकों की धारणा पर असर डाला।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 102.57 अंक यानी 0.13 फीसद गिरकर 80,502.08 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 504 अंक तक गिरकर 80,100.65 अंक पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 21.65 अंक यानी 0.09 फीसद की गिरावट के साथ 24,509.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 168.6 अंक गिरकर 24,362.30 अंक पर आ गया था। शेयर

केंद्रीय बैंक हर दो महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आधार पर नीतिगत दर तय करता है। इसमें भोजन, ईंधन, विनिर्मित सामान और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं।

को खुदरा मुद्रास्फीति को दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक हर दो महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आधार पर नीतिगत दर तय करता है। इसमें भोजन, ईंधन, विनिर्मित सामान और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार करना चाहिए। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। उल्लेखनीय है

बाजारों में गिरावट का यह लगातार दूसरा सत्र रहा। इसके पहले शुक्रवार को भी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए थे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, हालांकि, मंगलवार को पेश होने वाले बजट के अनुकूल रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बाजार के ऊंचे मूल्यांकन और कंपनियों के मुनाफे में गिरावट के जोखिम को देखते हुए निवेशकों की इस पर करीबी नजर बनी रहेगी। नायर ने कहा कि रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी के मुनाफे में गिरावट ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला।

बाजारों में गिरावट का यह लगातार दूसरा सत्र रहा। इसके पहले शुक्रवार को भी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए थे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, हालांकि, मंगलवार को पेश होने वाले बजट के अनुकूल रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बाजार के ऊंचे मूल्यांकन और कंपनियों के मुनाफे में गिरावट के जोखिम को देखते हुए निवेशकों की इस पर करीबी नजर बनी रहेगी। नायर ने कहा कि रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी के मुनाफे में गिरावट ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला।

## विदेश में बसे भारतीयों के धन प्रेषण में 3.7 फीसद की वृद्धि हुई

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया धन (रेमिटेंस) 2023 में 3.7 फीसद बढ़कर 124 अरब डॉलर हुआ। 2025 में इसके 129 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई। भारत के धन प्रेषण का प्राथमिक स्रोत तेल निर्यातक देश है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की सबसे अधिक प्रवासी आबादी है और यह सबसे ज्यादा धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है।

भारत में 2023 में 120 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में 2024 के लिए धन प्रेषण का परिदृश्य मजबूत है। इसमें 3.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इसमें कहा गया कि भारत की प्रवासी आबादी में अधिकतर उच्च आय वाले ओईसीडी बाजारों में कार्यरत उच्च कुशल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा तथा जीसीसी बाजारों में कार्यरत कम कुशल प्रवासी शामिल हैं।

## 'चीन से विदेशी निवेश से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ा सकता है भारत'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह बढ़ने से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसे पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं की सफलताओं और रणनीतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन अर्थव्यवस्थाओं ने आमतौर पर दो मुख्य रणनीतियों का अनुसरण किया है-व्यापार लागत को कम करना और विदेशी निवेश को सुगम बनाना।

इसमें कहा गया कि भारत के पास 'चीन प्लस वन' रणनीति से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प हैं- या तो वह चीन की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो जाए या फिर चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि इन विकल्पों में से चीन से एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका को भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अधिक आशाजनक प्रतीत होता है, जैसा कि पूर्व में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने किया था।

## 'सरकारों को कुछ शक्तियां छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में सरकारों को अपनी कुछ शक्तियों का त्याग करने का सुझाव देते हुए कहा गया है कि ऐसा करना 'शासन करने वाले और शासित दोनों' के लिए अच्छा होगा।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, आने वाली चुनौतियों पर विचार करते समय किसी को भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी है। समीक्षा कहती है, 'हमने एक लंबा सफर तय किया है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1992-93 के लगभग 288 अरब डॉलर के स्तर से बढ़कर 2022-23 में 3.6 लाख करोड़ डॉलर हो गई।' लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन प्रावधानों की वजह से सरकार के सभी स्तर के कारोबार पर बोझ पड़ता है।

**ई-निविदा सूचना** अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विद्युत वितरण मण्डल- कामपुर देहात के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य हेतु अनुभवी व सक्षम निविदादाताओं द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, निविदा सम्बन्धी पूर्ण सूचना एवं ई-निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टेंडर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है। -  
**क्र.सं 1, ई-0- निविदा सं०: 15/वि०वि०मं०का०दे०/2024-25, विवरण: विद्युत वितरण खण्ड- रनियां के अन्तर्गत जवाहर नवीदय विद्यालय, जैनपुर के मोडिरी सिस्टम को एल०टी० से एच०टी० में परिवर्तित करने के कार्य के अन्तर्गत 100 के०वी०ए० परिवर्तक की स्थिति व फेसिंग एवं अर्थिम का कार्य, क्र०सं०: 2, ई-0- निविदा सं०: 16/वि०वि०मं०का०दे०/2024-25, विवरण: विद्युत वितरण खण्ड-रनियां के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कुम्भी को नया 1600 के०वी०ए० का संयोजन निर्माण करने का कार्य। हस्ता./- (अधीनस्थ अभियन्ता) वि०वि० मण्डल कामपुर देहात, प्रशाक संख्या: 1742/वि०वि०मं०का०दे०/प्रकाशन दिनांक : 22/07/2024**

**ऋण वसूली अधिकरण-II दिल्ली**  
 4था जीवन ऋण बिलिडन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के संसद ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) विभागवली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के अन्तर्गत केवाई तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अभियन्ता, 1993 की धारा 19(4) के अन्तर्गत सूचना  
 ओए/581/2023 तिथि : 10.07.2024  
**एचडीएफसी बैंक** **वनाम** **आवेदक**  
**अर्जित शाह ( सै. एयरकॉर एक डायरेक्टर के प्रपि.)** **प्रतिवेदी**  
 सै.मं.डी-1, श्री अर्जित शाह, पुर की अर्जित शाह, प्लॉट नं. 212, नमो नं. 10 एच 10, एनएच पारसी, दक्षिण दिल्ली-74, पता ही नं. पारत नं.व/नं. 332 नवीएच, फ्लैट नं. 204, शिव बाजार मार्ग, नई दिल्ली-16, पता ही नं. वीरचन्द्र-24, प्रयाग नगर, नवीधु टाउन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र लिडि-II मुम्बई नगर-122018  
 बैंक कि कर नमिन आवेदक ने रु. 1,05,45,574.72/- (रु. एक करोड़ पाँच लाख बसिन्स हजार पाँच को पचास सैके हजार साठ) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला चला किया है तथा बैंक कि इस अधिकरण की संरुष्टि के लिये यह स्थिति हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व कर्जा संचय नहीं है। अतएव, अधिकरण के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपके निदेशों की पूर्णता हेतु कि 16.10.2024 को 10.30 पूर्वा. में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।  
 (यहां रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपके अनुपस्थिति में ही की जायेगी।)  
 सभी मामलों पर विचार विधिबोध काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य हेतु:  
 i) सभी अधिकता/व्यवधान लिस्तेको वेबएप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।  
 ii) मानकीय पीठान्तरित अधिकारी / सिस्टमर के द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये निर्देशों/आदेशों तथा पारदर्शक डीआरटी के अधिकृतिक पोर्टल [anrt.drt.gov.in](http://anrt.drt.gov.in) पर स्वयं दैनिक जांच कर लिस्ट में उपस्थित हों।  
 iii) किसी प्रकार की आसक्तिमताओं के लिये अधिकृतिक विलय प्रयोग नं. 23748478 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।  
 संरे हाथ से तथा अधिकरण की पूर्ण जानकारी के लिये 10 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक अधिकरण के आदेश से संकेतन अधिकारी डीआरटी-II दिल्ली

**जना स्माल फाइनेंस बैंक**  
 (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)  
 क्षेत्रीय शाखा कार्यालय : जी-01, भूतल, साइबर हाइड्रेस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010  
**सर्पेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना**

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों की बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चुक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन आस्थितियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदारों के लिये प्राविष्ट हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रवर्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कालम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का भुगतान करना को कहते हुए मांग सूचना निम्न की थी, किन्तु उनमें से कुछ के साथ विधिन कारणों से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता नं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत का विवरण	परिपूर्य की तिथि एवं मांग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1	1) श्री सैकुलहास खान (कर्जदार) 2) श्रीमती नजमा (सह-कर्जदार एवं बंधककर्ता)	ऋण खाता नं. 46128420000059 46128420000036 तथा 461284120000030 ऋण राशि : रु.5,50,000/- और रु.5,00,000/- कुल रु.10,50,000/-	निजी रखाई गई अचल संपत्ति: संपत्ति का विवरण: भकान नंबर 1190 के अंतर्गत संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मीटर है, यानी 65 वर्ग गज, खसरा नंबर 61-मिन और 65, यूसु हावाड़ी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-226024 पर स्थित। स्थानिय श्रीमती नजमा, पत्नी श्री शाफीक अहमद के पास है। सीमा: उत्तर: 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: अन्य का प्लॉट, पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट।	परिपूर्य की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि 16.07.2024	14.07.2024 तक रु. 19,94,864.60 (सर्वे नवीन सख्त यौनिक हस्तार आर जी बैंकर और साठ फीस मात्र)

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम सं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूत हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंसियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का एक उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाहण रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्ण अनुमति के बिना उपलब्ध प्रतिभूत को निरन्तरित करने या अन्यवहार करने अथवा विक्री, परदे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।

तिथि : 23.07.2024 स्थान : मेरठ

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



www.greenlamindustries.com

## ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ों में)

	स्टैंडएरल		कंसोलिडेटेड			
	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1. प्रचालनों से कुल आय	525.75	488.97	2123.50	604.71	515.24	2306.35
2. अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादित मद से पूर्व)	30.27	37.14	188.98	27.05	43.67	184.94
3. अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व तथा अपवादित मद के पश्चात)	30.27	37.14	188.98	27.05	43.67	184.94
4. अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पश्चात तथा अपवादित मद के पश्चात)	23.23	28.01	145.89	19.89	33.00	138.01
5. कुल व्यापक आय	21.73	25.85	144.59	18.38	30.90	137.67
6. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	12.76	12.70	12.76	12.76	12.70	12.76
7. आरक्षितियाँ (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	1033.58	-	-	1064.41
8. प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	194.99	-	-	194.99
9. नेट वर्थ	1058.73	937.10	1036.18	1079.34	962.44	1063.42
10. प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	92	99	99	257	144	234
11. बकाया विमोचनीय अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
12. ऋण इक्विटी अनुपात	0.29	0.21	0.25	0.84	0.54	0.77
13. आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक) (रु. में)	1.82*	2.20*	11.44	1.56*	2.59*	10.82
14. पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित	-	-	0.69	-	-	0.69
15. ऋणपर रिडेम्पशन आरक्षित	-	-	-	-	-	-
16. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	1.40	3.23	1.55	1.03	3.47	1.35
17. व्याज सेवा कवरेज अनुपात	6.89	9.27	8.68	5.30	10.30	7.74
18. कार्यशील पूंजी हेतु दीर्घकालिक ऋण (गुना)	0.60	0.74	0.68	1.88	1.41	1.91
19. खालू प्रचालन (गुना)	1.20	1.57	1.16	1.38	1.38	1.21
20. खाता अनुपात के अशोध ऋण (%)	0.03	0.16	0.25	0.32	0.31	0.14
21. खालू देयता अनुपात (गुना)	0.07	0.31	0.36	0.05	0.14	0.33
22. सफल आस्थितियों के कुल ऋण (%)	21.40	22.81	21.24	36.89	31.89	36.51
23. देनदार का टर्नओवर (दिन)	27	24	24	25	25	23
24. इन्वेंट्री टर्नओवर (दिन)	84	90	80	93	93	89
25. प्रचालन मार्जिन (%)	10.50	11.73	12.49	10.24	12.27	12.47
26. निवल लाभ मार्जिन (%)	4.42	5.97	6.87	3.29	6.40	5.98

\*वार्षिकीकृत नहीं

- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट [www.greenlamindustries.com](http://www.greenlamindustries.com) पर भी उपलब्ध है।
- सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मदों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रासंगिक प्रकटन किए गए हैं और ऊपर बताई गई उनकी वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है।
- कंपनी के पास उपरोक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण मद नहीं है।
- उपरोक्त अवधि के दौरान कंपनी ने अपना कोई भी परिचालन बंद नहीं किया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

सौरभ मित्तल

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[डीआईएन: 00273917]

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 2024

कारपोरेट पहचान संख्या: L21016DL2013PLC386045

पंजीकृत तथा कारपोरेट कार्यालय : 203, 2<sup>nd</sup> फ्लोर, वेस्ट विंग, वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट,

हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली- 110037, भारत फोन: +91-11-42791399;

ईमेल: [investor.relations@greenlam.com](mailto:investor.relations@greenlam.com); वेबसाइट: [www.greenlamindustries.com](http://www.greenlamindustries.com)



**द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड**  
 (CIN: L74899DL1937PLC000478)  
 पंजीकृत कार्यालय: 86, जयपुर, नई दिल्ली-110001(भारत)  
 ईमेल: [delsafe@dsdgroup.co.in](mailto:delsafe@dsdgroup.co.in), वेबसाइट: [www.dsdgroup.co.in](http://www.dsdgroup.co.in)  
 फोन: 011-43580400, 23320084, 23321902  
**शेयरधारकों को सूचना**  
**विषय: कंपनी के दावा न किए गए लाभांश और इंडिविडुअल शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) के डीमैट खाते में स्थानान्तरित करना।**  
 यह सूचना निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानान्तरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।  
 उपर्युक्त नियमों में उन शेयरों से निपटने का तरीका निर्धारित किया गया है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अदा न किया गया हो/अप्रदत्त किया गया हो। उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शेयरों को अदा न किए गए/अप्रदत्त लाभांश के साथ निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाएगा। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट [www.dsdgroup.co.in](http://www.dsdgroup.co.in) पर अपलोड की जा रही है। नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना पत्र भी भेजे जा रहे हैं जिन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 7 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2016-17 से अपने लाभांश को भुनाया नहीं है और यह सूचना तदनुसार जारी किया जा रहा है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 302 कृष्ण बाजार, 32-33, नेहरू रोड, नई दिल्ली-110019 फोन नंबर + 91-11-42425004, ईमेल: [bssdelhi.bd@bigshareonline.com](mailto:bssdelhi.bd@bigshareonline.com) को लिखें।  
**द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड**  
 हस्ता./-  
**विजय कुमार गुप्ता**  
 प्रबंध निदेशक/सीईओ  
 डीआईएन 00243413  
 स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 19/07/2024

**मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड**  
 सीआईएन: L74899DL1993PLC056421  
**पंजीकृत कार्यालय** : ए-30, एर-11, दूसरी मंजिल, कैलास कॉलोनी, नई दिल्ली - 110048  
 ई-मेल : [pgindustry93@gmail.com](mailto:pgindustry93@gmail.com), वेबसाइट : [www.pgil.com](http://www.pgil.com)  
**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओवीएम) और ई-वोटिंग निर्देशों के माध्यम से आयोजित होने वाली 02/2024-25 असाधारण आम बैठक के संबंध में मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यान के लिए सूचना**  
 एतद्वारा सूचित की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीई") और भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के अनुसार सूचनाओं के साथ पत्रित सूची (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों की पूर्ण करने के लिए मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 02/2024-25 असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को सुबह 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी।  
 सदस्य वीसी / ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को ईजीएम में उपस्थित माना जाएगा और उनकी उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।  
 प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, व्याख्यात्मक विवरण और उसके साथ अंतिम किए जाने वाले अंश दर्शाए जाने के साथ, प्रकाशन, 22 जुलाई, 2024 को केवल ईमेल द्वारा कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक पंजीकृत हैं।  
 सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [www.pgil.com](http://www.pgil.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेवनाल सिक्वोरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।  
 सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संचालने और उसकी निगरानी करने बैठक और वोटिंग आदि से संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग के लिए के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सदन केवल वीसी/एवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने और भागीदारी के तरीके के बारे में सूचना में निदेश दिए गए हैं।  
**ईमेल पते पंजीकृत/अप्रदत्त करने का तरीका:**  
 ईमेल पते पंजीकृत/अप्रदत्त करने का तरीका:  
 (क) भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ बैंक की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख हो, जिसे ईमेल द्वारा कंपनी के ईमेल पते [pgindustry93@gmail.com](mailto:pgindustry93@gmail.com) पर या आरटीए के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है।  
 (ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अप्रदत्त करें।  
 कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 7 अगस्त, 2024 को शेयर धारण करता है, वह ईजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से पूरा आईडी और पारदर्शक प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी की वेबसाइट [www.pgil.com](http://www.pgil.com) पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य ईजीएम की सूचना में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।  
**रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:**  
 निम्न (प्रवर्धन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के साथ पत्रित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेवनाल सिक्वोरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और बैठक के दौरान सुरक्षित तरीके से ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संचालने और उसकी निगरानी करने बैठक और वोटिंग आदि से संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग के लिए के लिए वीसी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स एमएस सर्विसेज लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।  
 2. बैठक की सूचना ऐसे सभी इक्विटी शेयरधारकों को भेजी जा रही है, जो कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक शेयर धारण करते हैं।  
 3. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों और अन्य सभी व्यक्तिगतों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों का ईमेल पता कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, और जो इस ईजीएम की सूचना और कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजे गए अन्य सभी संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करवा सकते हैं।  
 4. भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ बैंक की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख हो, जिसे कंपनी के ईमेल पते [pgindustry93@gmail.com](mailto:pgindustry93@gmail.com) पर या आरटीए के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है।  
 5. डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से ईमेल पते को अपडेट कर सकते हैं।  
 6. डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल द्वारा वोटिंग का तरीका ईजीएम की सूचना में दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट [www.pgil.com](http://www.pgil.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी वीएसई लिमिटेड की [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेवनाल सिक्वोरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध हैं।  
**रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:**  
**रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत:** 11 अगस्त, 2024 को सुबह 09:09 बजे (भा.मा.स.)  
**रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति:** 13 अगस्त, 2024 को सुबह 05:00 बजे (भा.मा.स.)  
 उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।  
 जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ईजीएम में दौबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 7 अगस्त, 2024 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।  
 किसी भी सभ के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders** के अंतर्गत **10-20-voting user manual for Shareholders** डाउनलोड कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 18001020090 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं, या उपाध्यक्ष, श्री अमित विशाल को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर निवेदन कर सकते हैं।  
 कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स समीर भटनागर एंड कंपनी, प्रिवेटिंस कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोप्राइटर, समीर किशोर भटनागर, प्रिवेटिंस कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या ए-30997) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया को जांच करने के लिए स्कैनिंग/ऑडिट के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने नियुक्त किए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और वे इसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।  
 ई-वोटिंग के परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.pgil.com](http://www.pgil.com) पर अपलोड की जाएगी और वीएसई लिमिटेड को सूचित की जाएगी, जब कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हों।  
 सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में ई-वोटिंग (इंस्टा पोल) के माध्यम से वोट डालने का तरीका को ध्यान से पढ़ें।

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड

हस्ता./-

दिनांक: 22.07.

## ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर मस्क और खोसला में जुबानी जंग

न्यूयार्क, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर अरबपति टेक कारोबारी एलन मस्क और भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति विनोद खोसला के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में खोसला ने ट्रंप को एक ऐसा रिपब्लिकन नेता करार दिया, जिसमें कोई 'कोई नैतिकता नहीं है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, महिलाओं का अपमान करता है' और उनके जैसे प्रवासियों से 'नफरत करता है।' खोसला ने कहा कि उनके लिए ट्रंप जैसे व्यक्ति का समर्थन करना बहुत मुश्किल है। भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति ने सवाल किया, 'वह मेरे करों में कटौती कर सकते हैं या कुछ विनियमन में राहत दे सकते हैं, लेकिन यह उनके व्यक्तिगत मूल्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता। क्या आप एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं, जो अपने पहले वर्ष में जलवायु प्रगति को एक दशक पीछे धकेल दे? क्या आप अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते समय उदाहरण के रूप में उन्हें पेश करना चाहते हैं?' खोसला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा कि ट्रंप आपसे नफरत नहीं करते हैं। अलबत्ता, वह आपको पसंद करते हैं। उनसे मिलिए और अपने बारे में उनके विचार जानिए।

ट्रेला और स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रशासन होना चाहिए, जिसके योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण होने और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के मुकाबले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की संभावना ज्यादा हो।

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा चुनाव मैदान से हटने की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने का दरवाजा कई दावेदारों के लिए खुल गया है। प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैसी पेलेसी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया।

राष्ट्रपति बाइडेन ने पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है और कई अन्य प्रमुख डेमोक्रेटिक नेता भी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में आगे आए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी में उनकी उम्मीदवारी का रास्ता कितना आसान होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के प्रमुख दावेदारों की सूची इस प्रकार है : कमला हैरिस कैलिफोर्निया के आकलैंड में जन्मी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नागरिक अधिकार वकील एवं न्यायविद दिवंगत थरुड मार्शल को प्रेरणास्रोत मानती हैं और अपने जीवन पर नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े रहे अपने माता-पिता के प्रभाव का अकसर जिक्र करती हैं। लास एंजलिस के वकील डगलस एमहाफ कमला हैरिस के पति हैं। बाइडेन ने 2020 में हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हुए उन्हें 'निडर योद्धा' कहा था। कमला जनवरी 2021 से उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रही हैं। वह अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली ऐसी नागरिक हैं जो इस पद पर आसीन हुई हैं। इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रिट्ज़कर अमेरिका में पद पर आसीन सबसे अमीर नेता हैं। वह 'हवा होटल' के उन्नाधिकारी एक पूर्व निजी इन्वेंशन और परोपकारी हैं। उनकी कुल संपत्ति 3.4 अरब अमेरिकी डालर है। उन्हें 'फोर्ब्स 400' की सबसे



अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने देश से प्यार करने वाला 'महान व्यक्ति' बताते हुए विश्व नेताओं ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनके साहसिक कदमों और वैश्विक नेतृत्व के लिए सोमवार को उनका आभार व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले का सम्मान करते हैं और उनके श्रेष्ठ कार्यकाल में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने

अमीर अमेरिकियों की सूची में 250वें स्थान पर रखा गया।

ग्रेचेन व्हिटमर मिशिगन की गवर्नर हैं। वह राज्य विधायिका में डेढ़ दशक तक सेवाएं देने के बाद 2018 में गवर्नर पद के चुनाव में पहली बार जीत हासिल कर डेमोक्रेटिक पार्टी में तेजी से उभरीं। गेविन न्यूजाम कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजाम सैन फ्रांसिस्को के मूल निवासी हैं, जो 1995 में मेयर पद के लिए विली ब्राउन के प्रचार अभियान में स्वयंसेवक के तौर पर राजनीति में शामिल हुए थे। मेयर ब्राउन ने दो साल बाद न्यूजाम को 'सैन फ्रांसिस्को बोर्ड आफ सुपरवाइजर्स' की एक खाली सीट पर नियुक्त किया और बाद में उन्हें इस सीट पर पुनर्निर्वाचित किया गया। न्यूजाम ने बाद में मेयर पद का चुनाव जीता और 2004 में सैन फ्रांसिस्को क्लर्क को समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने का निर्देश देकर वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। पेनसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शिपरो को पार्टी का एक उभरता नेता माना जाता है। उन्होंने गवर्नर पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी थी। वह अटॉर्नी जनरल के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं।

## विश्व नेताओं ने बाइडेन का उनके 'वैश्विक नेतृत्व' व 'मित्रता' के लिए आभार जताया

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने देश से प्यार करने वाला 'महान व्यक्ति' बताते हुए विश्व नेताओं ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनके साहसिक कदमों और वैश्विक नेतृत्व के लिए सोमवार को उनका आभार व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले का सम्मान करते हैं और उनके श्रेष्ठ कार्यकाल में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने

## 'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदला गया

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

बाइडेन की घोषणा के तुरंत बाद रविवार को 'एक्स' पर 'बाइडेन एचक्यू' खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया। प्रचार अभियान दल अपने संदेशों को प्रसारित करने और प्रतिद्वंद्वियों के हमलों का जवाब देने के लिए इस खाते

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

का इस्तेमाल करता है। 'सीएनएन' ने बताया कि बाइडेन-हैरिस अभियान के लिए 'एक्स' पर सोशल मीडिया त्वरित प्रतिक्रिया खाते 'बाइडेन एचक्यू' का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

बाइडेन के फैसले के बाद डेमोक्रेटिक कन्वेंशन नियम समिति बुधवार को नामांकन की रूपरेखा पर चर्चा करेगी।

## खबर कोना



बांग्लादेश के ढाका में सरकारी नौकरी कोटा के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जले वाहनों के पास से गुजरते सुरक्षाकर्मी।

## बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात शांत पर इंटरनेट सेवा ठप

ढाका, 22 जुलाई (एपी)।

बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद सरकारी नौकरियों से जुड़ी विवादस्पद कोटा प्रणाली को वापस लेने के फैसले से हालात शांत होने के बावजूद इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अब भी ठप हैं। सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है और केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। देश में कुछ दिन पहले ही देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया था और सैन्यकर्मी राजधानी और अन्य क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे। देश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

## इजराइल ने गाजा के मानवीय क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया

दीर अल-बलाहा, 22 जुलाई (एपी)।

इजराइली सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में उस हिस्से को खाली करने का सोमवार को आदेश दिया जिसे उसने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। सेना ने कहा कि वह हमला के आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जो इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं और इसका इस्तेमाल इजराइल की ओर राकेट छोड़ने के लिए किया है। इस इलाके में मुवासी मानवीय क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा शामिल है जो दक्षिणी गाजा पट्टी पर स्थित है। इस महीने की शुरुआत में, इजराइल ने कहा था कि उसका अनुमान है कि कम से कम 18 लाख फिलिस्तीनी अब मानवीय क्षेत्र में हैं।

## अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की हत्या के प्रयास मामले में सीक्रेट सर्विस की निवेशक से पूछताछ की

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

सीक्रेट सर्विस की निदेशक किबरले चीटल ने सोमवार को संसद में अपनी पेशी के दौरान कहा कि उनकी एजेंसी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के अपने मिशन में नाकाम रही। इस बीच, दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चीटल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तेरह जुलाई को हुए हत्या के प्रयास के मामले में संसद में अपनी पहली पेशी के दौरान, जांच जारी होने का हवाला देकर सवाल को बार-बार टाले जाने के कारण चीटल से सांसद नाराज नजर आ रहे थे। चीटल ने ट्रंप पर हुए हमले को दशकों में सीक्रेट सर्विस की 'सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता' करार दिया।

## 'रूसी मूल के अमेरिकी पत्रकार को गोपनीय सुनवाई करके दोषी करार दिया गया'

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित 'रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी' की रूसी मूल की अमेरिकी पत्रकार अलसु कुरमाशेवा को रूस की अदालत ने गोपनीय सुनवाई करके रूसी सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करने का दोषी करार दिया और साढ़े छह साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के दस्तावेजों और अधिकारियों से सोमवार को यह जानकारी प्राप्त हुई। कुरमाशेवा को काजान शहर की अदालत ने दोषी करार दिया। इसी दिन रूसी शहर येकतेरिनबर्ग की अदालत ने वाल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता इवान गेरशकोविच को जासूसी करने का दोषी करार देते हुए 16 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

## भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दे कूटनीति के जरिए सुलझाए जाएंगे : ओली

काठमांडू, 22 जुलाई (भाषा)।

नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों को कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से हल करने के लिए सहमत है और काठमांडू अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में 'स्पष्ट और दृढ़' है।

प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं। ओली ने कहा कि संघीय संसद और नेपाल सरकार

का रुख देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ है।

ओली ने कहा कि नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है, जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है और इसके अनुलग्नक तीन में उल्लेख किया गया है और हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति बनी है। ओली (72) ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान हुई मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी है।

## मैं केरल में मुसलिम संचालित शाकाहारी भोजनालय में जाता था : न्यायमूर्ति भट्टी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने भोजनालयों में साफ-सफाई की पैरवी करते हुए सोमवार को कहा कि केरल में तैनाती के वक्त वह एक मुसलिम द्वारा चलाए जा रहे शाकाहारी भोजनालय में अक्सर जाते थे क्योंकि वहां अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता था।

न्यायमूर्ति भट्टी ने अपना यह अनुभव तब साझा किया जब उन्होंने न्यायमूर्ति श्रिकेश राय के साथ मिलकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि जब मैं केरल में था तो मेरा अपना अनुभव और ज्ञान है।

## मोदी ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लक्जमबर्ग के अपने समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन से बात की और यूक्रेन में संघर्ष समेत क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता के समर्थक हैं। इस दौरान फ्रीडेन ने मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी।

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्जमबर्ग के उनके समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन ने फोन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री फ्रीडेन ने दुनिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली में भारत द्वारा निभाई जा रही भूमिका

की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि फ्रीडेन के साथ उनकी साहसिक बातचीत हुई और उन्होंने व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं व औद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्रों समेत भारत-लक्जमबर्ग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम क्षेत्रीय व वैश्विक शांति एवं स्थिरता का समर्थन करते हैं। वहीं, फ्रीडेन ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर उनकी कई मसलों पर बातचीत हुई। उन्होंने भारत को अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि शांति व स्थिरता की दिशा में काम करने के दोनों देशों के लक्ष्य समान हैं।

## वेबाक

खरगे ने आरोप लगाया कि 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा कर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी।

4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री ने 58 साल बाद,

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तार नेताओं को चुनाव के दौरान आभासी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति सुयंकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि यह याचिका गलत मंशा से दाखिल की गई है। यह एक नेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन बेहतरीन वकीलों के साथ इस

अदालत में पेश होते हैं।

श्रीष अदालत ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई जरूरी नहीं मानते जिसे कथित तौर पर जनहित में दाखिल किया गया है। खारिज की जाती है। न्यायालय विधि छात्र अमरजीत गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने

गिरफ्तार नेताओं को आनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इससे खूंखार अपराधियों, यहां तक कि भगोड़ा माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों और प्रचार के लिए खुद को पंजीकृत करने का मौका मिलेगा।

## कहा, संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से करेंगे छेड़छाड़

## कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर लगाया आरोप

## सरकारी कर्मियों को विचारधारा के आधार पर बांटना चाहते हैं

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाकर इन कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने वाले 1966 के आदेश को बदल दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नौ जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा



की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय

सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा कर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

यह सरकारी दफ्तरों में लोक सेवकों के निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। उन्होंने दावा किया कि

सरकार संभवतः ऐसे कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उसके संविधान बदलने की 'कुत्सित मंशा' को चुनाव में परास्त कर दिया। खरगे ने कहा कि चुनाव जीत कर संविधान नहीं बदल पा रहे तो अब पिछले दरवाजे सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे।

यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दिए गए उस माफोनामे व आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा।





राज्यसभा की कार्यवाही

# तीन साल में सरकार ने संसद में 913 आश्वासन दिए, 583 पूरे किए

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरगन ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया कि तीन साल में सरकार ने संसद में 913 आश्वासन दिए जिनमें से 583 का कार्यान्वयन किया जा चुका है और 330 लंबित हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत मुद्दे एवं संशोधनों सहित विभिन्न कारणों से आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी होती है।

मुरगन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन साल में 913 आश्वासन दिए गए। पिछले तीन साल में 583 का कार्यान्वयन किया गया। 330 अभी लंबित हैं।' उन्होंने कहा कि आश्वासनों को, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है, लेकिन उनमें से कुछ का समय पर कार्यान्वयन नहीं हो सका है और आश्वासन समिति से समय की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि 1956 से 2024 तक संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की दर 99 फीसद से अधिक रही है। मुरगन ने कहा कि इस अवधि के दौरान

राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को दोपहर करीब पीने तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को उच्च सदन की बैठक लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के एक घंटे बाद शुरू होगी। उच्च सदन के 265वें सत्र की पहली बैठक राद्गान की धुन बजाए जाने के साथ शुरू हुई। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

राज्यसभा में दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की दर 99.07 फीसद रही जबकि लोकसभा में यह दर 99.43 फीसद रही। इसी दौरान कांग्रेस सदस्य शक्तिसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों को लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं मिलता है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिज्जीजू ने कहा कि शिष्टाचार और सद्भावना के तहत सरकारी विभागों और मंत्रियों को पत्रों का जवाब देना चाहिए लेकिन ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है जिसके तहत किसी खास पत्र का

तथा वाईएसआर कांग्रेस सदस्य एस निरंजन रेड्डी को उनके जन्मदिन पर पूरे सदन की ओर से बधाई दी। सभापति ने वियतनाम के नेता गुयेन फू ट्रोंग और सदन के पूर्व सदस्य पी कन्नन के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई मुद्दे उठाए। इससे पहले सभापति ने सदन को सूचित किया।

जवाब देना जरूरी हो।

सरकार ने सोमवार को बताया कि घरेलू एअरलाइनों ने इस साल 31 मई तक 7,030 अनुसूचित उड़ानें रद्द की हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में एअरलाइनों को 4,56,919 अनुसूचित रवानगी उड़ानों का संचालन करना है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि 2022 में 6,413 उड़ानें रद्द की गईं।

## आपरेशन के बाद शरीर में सुई छूटने का मामला

# बीस साल बाद महिला को पांच लाख का मुआवजा

बंगलुरु, 22 जुलाई (भाषा)।

बंगलुरु के एक निजी अस्पताल में सर्जरी के बाद एक महिला के शरीर में 3.2 सेंटीमीटर की 'सर्जिकल' सुई छोड़ दिए जाने के लगभग 20 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि अस्पताल, पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए देगा।

कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल और दो चिकित्सकों को जयानगर निवासी पद्मावती को मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसने 'न्यू इंडिया एशोरस कंपनी लिमिटेड' को भी निर्देश दिया है कि वह 'पेशेवर और चिकित्सीय लापरवाही के कारण' महिला को पांच लाख रुपए का भुगतान करे। इस कंपनी ने ही 'पालिसी' जारी की थी।

**कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल और दो चिकित्सकों को जयानगर निवासी पद्मावती को मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।**

पिछले माह जारी किए गए आयोग के आदेश के अनुसार 29 सितंबर 2004 को दीपक अस्पताल के दो चिकित्सकों ने कथित तौर पर महिला की हर्निया की सर्जरी की थी और सर्जरी पूरी होने पर उसका 'अपेंडिक्स' भी हटा दिया गया था। सर्जरी के समय महिला की उम्र 32 वर्ष थी। इसके अगले दिन महिला ने गंभीर दर्द को शिकायत की तो उसे कुछ दर्द निवारक दवाएं दी गईं। उसे आश्वासन दिया गया कि यह सर्जरी के बाद की परेशानी है और ठीक हो जाएगी। आदेश में कहा गया है कि महिला को कई वर्षों

तक पेट और पीठ में तेज दर्द का सामना करना पड़ा और बाद में उसे दो बार उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पद्मावती, 2010 में बंगलुरु के ही एक अन्य निजी अस्पताल में पहुंची जहां जांच के दौरान पता चला कि उसके पेट और शरीर के पिछले हिस्से में कोई बाहरी चीज (सर्जिकल सुई) मौजूद थी। महिला को उसे निकलवाने का कहा गया। इसके बाद महिला की फिर से सर्जरी की गई और उसके शरीर से 3.2 सेंटीमीटर की सर्जिकल सुई को निकाला गया। इसके बाद अगले वर्ष महिला ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई।

आदेश में कहा गया, 'निश्चित रूप से सर्जिकल सुई निकाले जाने तक उसे गंभीर दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ा।' इसमें कहा गया कि इसलिए वह पांच लाख रुपए का 'मुआवजा' पाने की हकदार है और बीमा कंपनी को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

## जयशंकर ने कहा, मिस्र भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग में लगातार विविधता लाई जा रही है और दोनों पक्ष इसे और बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 50 से अधिक भारतीय कंपनियां पहले ही मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर चुकी हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा मुख्य क्षेत्र हैं। जयशंकर ने मिस्र को भारत का 'महत्वपूर्ण

रणनीतिक साझेदार" करार दिया।

उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक सहयोग में लगातार विविधता लाई जा रही है। दोनों पक्ष पारस्परिक लाभ के लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि हमारा आइटी उद्योग भी ऐसी साझेदारी कर रहा है और आने वाले समय में हम इसके बढ़ने की उम्मीद है। मिस्र भी हमारे कृषि-निर्यात के लिए एक बाजार के रूप में खुल गया है, विशेष रूप से गेहूं के निर्यात के लिए। विदेश मंत्री मिस्र के 'राष्ट्रीय दिवस' का जश्न मनाने के लिए भारत स्थित उसके दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

## 'हरियाणा के विधायक पंवार, इनेलो के पूर्व विधायक चलाते हैं अवैध खनन'

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस के विधायक सुरेन्द्र पंवार और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, उनके परिवार के सदस्य और सहयोगी राज्य के यमुनानगर जिले में एक अवैध खनन गिरोह चलाते हैं, जिसने 500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है।

हरियाणा की सोनीपत विधानसभा सीट से विधायक पंवार को पिछले सप्ताह संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल

ईडी की हिरासत में हैं। ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद जनवरी में दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला मुबारकपुर रायल्टी कंपनी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली रायल्टी कंपनी, जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएस बिल्डटेक और विभिन्न स्टोन क्रशर जैसी खनन पट्टाधारक कंपनियों द्वारा यमुनानगर में रेत, पत्थर और बजरी के अवैध खनन की जांच के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से संबंधित है।

## विशेष राज्य की मांग पर ऐसा होता रहा तो 'अंतरात्मा जाग जाएगी': कांग्रेस

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

कांग्रेस ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर सोमवार को कटाक्ष किया कि अगर ऐसा ही होता रहा तो 'अंतरात्मा जाग जाएगी'। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज (सोमवार को) लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है।

## विपक्ष पर वित्तमंत्री का तंज, कहा कि मेरा माइक भी होता है बंद

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एकाएक केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का माइक तकनीकी कारणों से बंद हो गया। इस पर चुटकी लेते ही वित्तमंत्री ने कहा कि मेरा भी माइक बंद होता है। इसे सीधेतौर पर विपक्षी सांसदों द्वारा बार- बार माइक बंद करने के आरोप के तंज के तौर पर देखा गया।

बीते सत्र में माइक बंद करने के मसले पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया गया है, जिस पर बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थिति को स्पष्ट किया था। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान निर्मला सीतारमण केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब दे रही थीं। इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया था। उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा किया और कहा कि अब तो आपको संतुष्टि मिल गई होगी। इसके बाद सांसदों ने भी इस तंज पर सदन में जमकर ठहाके लगाए।

प्रश्नकाल में न्यायाधिकरणों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया था। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को भी सदन के सदस्यों को यह बताना पड़ा था कि उनके पास किसी



**तकनीकी दिक्कत से बंद हो गया था एकाएक माइक। पहले सत्र के दौरान लगे थे नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद करने के आरोप।**

भी सदस्य के माइक बंद करने का कोई बटन नहीं होता है

सोमवार को लोकसभा सदन के दौरान कंपनी कानून के तहत लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने को लेकर एक सवाल आया था। इस मामले में सवाल-जवाब में पूछे गए पूरक प्रश्न के दौरान ये हालात पैदा हुए। मामलों में वित्तमंत्री का कहना था कि सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और लगातार लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सदन के समक्ष उन्होंने मामलों की संख्या में आई कमी का एक आंकड़ा भी सदन में पेश किया।

## कांग्रेस नीट-यूजी और अग्निपथ पर संसद में सरकार को घेरेगी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह ने सोमवार को बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि संसद सत्र में मॉडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितता, किसानों की समस्याओं और अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में मणिपुर की स्थिति और जम्मू-कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार शाम इंडिया गटबंघन की बैठक होगी। इसमें संसद के वर्तमान सत्र के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी

के आवास पर हुई पार्टी के रणनीतिक समूह की बैठक में सोनिया के अलावा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी और कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस संसद में नीट पर चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि हम कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में भी इसे रखेंगे। तिवारी ने कहा कि इस सत्र में कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दे, नीट और अग्निपथ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। बजट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि किसानों का भला हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, सरकारी कर्मचारियों को आयकर सीमा में छूट दी जाए और महिलाओं के लिए बात हो।

## ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि/संचालन अवधि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

रेलगाड़ी संख्या	स्टेशन से	स्टेशन तक	चलने के दिन	पूर्व अधिसूचित तिथि	विस्तार की अवधि	फेरे
03255	पटना जं.	आनंद विहार ट.	बीर, रवि	28.07.2024	01.08.2024 से 29.09.2024	18
03256	आनंद विहार ट.	पटना जं.	शुक्र, सोम	29.07.2024	02.08.2024 से 30.09.2024	18
02391	पटना जं.	आनंद विहार ट.	रविवार	27.07.2024	03.08.2024 से 28.09.2024	9
02392	आनंद विहार ट.	पटना जं.	रविवार	28.07.2024	04.08.2024 से 29.09.2024	9
03257	दानापुर	आनंद विहार ट.	रविवार	28.07.2024	04.08.2024 से 29.09.2024	9
03258	आनंद विहार ट.	दानापुर	सोमवार	29.07.2024	05.08.2024 से 30.09.2024	9

शेष पूर्ववत् है

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों की विस्तृत समय-सारणी और श्रेणियों की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट <https://enquiry.indianrail.gov.in> देखें अथवा NTES App देखें।

	<b>रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139</b>	<b>रेलमदद वेबसाइट देखें :-</b> <a href="http://www.railmadad.indianrailways.gov.in">www.railmadad.indianrailways.gov.in</a>		<b>उत्तर रेलवे</b> आपकी सुविधा - हमारा ध्येय <a href="http://www.nr.indianrailways.gov.in">www.nr.indianrailways.gov.in</a> पर मिलें
--	---------------------------------	--	--	--

गाहकों की सेवा में मुरकान के साथ

## गर्भवती का शव व दो बच्चों को जिंदा नदी में फेंकने के दो आरोपी गिरफ्तार

पुणे, 22 जुलाई (भाषा)।

पुणे में एक महिला का शव और उसके दो बच्चों को जिंदा इंद्रायणी नदी में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति तथा उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। पिंपरी चिंचवड थाने के अधिकारी ने बताया कि गर्भवती महिला की उस समय मौत हो गई थी जब उसके प्रेमी और मुख्य आरोपी गजेंद्र दगडखेरे ने उसे गर्भपात के लिए मुंबई के निकट ठाणे भेजा था।

## 'सेबी को चुनाव नतीजों वाले दिन शेयरों की अनुचित खरीद-बिक्री की जानकारी नहीं मिली'

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को आम चुनाव के नतीजों वाले दिन चार जून को शेयर बाजार में हुई गिरावट में किसी भी 'अनुचित खरीद-बिक्री' की कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। उस दिन अरबों निवेशकों की संपत्ति डूब गई थी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या यह सच है कि आम चुनाव-2024 के नतीजों के तुरंत बाद शेयर की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट आई और निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या यह सच है कि सेबी द्वारा मामले की जांच का अनुरोध किया गया था।

चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि

**वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि शेयर बाजार में उठापटक निवेशकों की धारणाओं के साथ-साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।**

हालांकि सेबी को उपरोक्त शेयर बाजार में उठापटक के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन किसी भी अनुचित व्यापार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। तीन जून को एरिजट पोल में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत की भविष्यवाणी के बाद शेयर बाजार 3.4 फीसद बढ़कर नए शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि, एक दिन बाद, शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई और सूचकांक 4,390 अंक या लगभग छह फीसद टूट गया। यह चार साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी।

	<b>केन फिन होम्स लि.</b> एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, कैनारा बैंक के ऊपर, सेक्टर 10ए, गुडगाँव, फोन: Ph.: 0124-2370035, 7625079135 ईमेल: <a href="mailto:gurgaon@canfinhomes.com">gurgaon@canfinhomes.com</a> CIN : L85110KA1987PLC008699
<b>कच्चा सूचना [नियम 8(1)]</b>	
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत केन फिन होम्स लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है और नियम 3 के साथ पंजित धारा 13(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक 03-05-2024 को एक नया नोटिफ जारी किया जिसमें चारखर्चों की अपरसीत सिंह मल्ला पुत्र श्री निरेंद्र सिंह मल्ला और श्रीमती बंदन दीप कोर पत्नी श्री अपरसीत सिंह मल्ला और बलविंदर सिंह पुत्र गुरु प्रकाश सिंह (गारुड) को नोटिफ में जल्लिखित शक्ति रु. 34,53,165/- (रुपए बौतीस लाख तिरपन हजार एक सौ पैंसठ मात्र) तथा उक्त नोटिफ की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक, संबिदात्मक दश पर अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकानी होगी।	
उपरोक्तकीं द्वारा गणित नुक़ाने में डिफ़रल वरुने पर, उपरोक्तकीं और सामान्य रूप से जनता को नोटिफ दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुस्था हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्ज़ा 17 जुलाई 2024 को कर दिया है।	
सुरक्षित संपत्तियों को नुक़ाने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में, उद्योक्तकीं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है कि ये संपत्ति की विशेष रूप से उपरोक्तकीं और सामान्य रूप से जनता को आग़ाह किया जाता है कि ये संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन रु. 34,53,165/- (रुपए बौतीस लाख तिरपन हजार एक सौ पैंसठ मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के लिए सीएफएएल के शुल्क के अधीन होगा।	
<b>अवल संपत्ति का विवरण</b>	
प्लॉट नंबर-105, कडक एरिया 860 वर्ग फीट, प्रथम तल पीछे की ओर, प्लॉट नंबर 486/8 और 483/8 (नया नंबर 536/12) खरसा नंबर 4148/3471/791, एन एन रेजीडेंसी, गावा की कोठी के पास, कृष्णा कॉलोनी, गुरुग्राम 122001 (हरियाणा)	
संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:	
उत्तर प्लॉट नं 106 पूर्वी मार्ग / प्लॉट नं 102	दक्षिण: प्लॉट नं 104 पश्चिम: खुला / प्लॉट नं 107
तिथि: 22.07.2024 स्थान: गुरुग्राम	हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

This advertisement is for information purpose only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, hold or sell securities and nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 10, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") BSE Limited ("BSE") and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations).



# INDOWIND ENERGY LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: L40108TN1995PLC032311

Our Company was incorporated as "Indowind Energy Private Limited" on July 19, 1995, as a private limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Chennai. The Registered Office of our Company is situated at Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai, Tamil Nadu 600 034. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" on September 30, 1997, vide an amended certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Chennai.

Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India, Contact person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer  
Telephone: 044-28331310 | E-mail id: bsharath@indowind.com | Website: www.indowind.co.in

## PROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI, INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 2,14,66,956 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹22.50 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹12.50 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹4,830.06 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS TUESDAY, JULY 16, 2024 (THE "ISSUE").  
#Assuming full subscription.

**FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF INDOWIND ENERGY LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" ONLY)**

The entire Issue Price of Rs. 22.50/- (including premium of Rs. 12.50/-) shall be payable on application. For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 326 of the Letter of Offer.

### ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE OF ON-MARKET RENUNCIATIONS*	ISSUE CLOSURES ON**
FRIDAY, JULY 26, 2024	WEDNESDAY, JULY 31, 2024	MONDAY, AUGUST 05, 2024

\* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

# Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS 2.25 TIMES TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

#### ASBA\*

Simple, Safe, Smart way of making an Application – Make use of it!!!

\* Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.

#### PROCESS OF MAKING AN APPLICATIONS IN THE ISSUE:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars, all Investors desiring to make an Application in the Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

The Application Form can be used by the Eligible Equity Shareholders as well as the Renouncees, to make Applications in the Issue basis the Rights Entitlement credited in their respective demat accounts or demat suspense escrow account, as applicable. For further details on the Rights Entitlements and demat suspense escrow account, see "Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 191 of the Letter of Offer.

Please note that one single Application Form shall be used by Investors to make Applications for all Rights Entitlements available in a particular demat account or entire respective portion of the Rights Entitlements in the demat suspense escrow account in case of resident Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form as on Record Date and applying in the Issue, as applicable. In case of Investors who have provided details of demat account in accordance with the SEBI ICDR Regulations, such Investors will have to apply for the Rights Equity Shares from the same demat account in which they are holding the Rights Entitlements and in case of multiple demat accounts, the Investors are required to submit a separate Application Form for each demat account.

Investors may apply for the Rights Equity Shares by submitting the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors are also advised to ensure that the Application Form is correctly filled up stating therein the ASBA Account in which an amount equivalent to the amount payable on Application as stated in the Application Form will be blocked by the SCSB.

Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details, see "Grounds for Technical Rejection" on page 187 of the Letter of Offer.

Our Company, the Lead Manager, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in the Issue by making plain paper Applications. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in the plain paper application and that Eligible Equity Shareholders making an application in the Issue by way of plain paper applications shall not be permitted to renounce any portion of their Rights Entitlements. For details, see "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" on page 183 of the Letter of Offer.

#### MAKING AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:

An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to [www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=Recognised&fpr=yes&intmid=34](http://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=Recognised&fpr=yes&intmid=34). Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

The Lead Manager, our Company, the directors, employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process.

**ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE I.e., TUESDAY, JULY 16, 2024**

#### MAKING AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS:

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, the Stock Exchanges or the Lead Manager.

An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Company, being Indowind Energy Limited;
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID;
- Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue;
- Number of Equity Shares held as on Record Date;
- Allotment option – only dematerialised form;
- Number of Rights Equity Shares entitled to;
- Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
- Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
- Total number of Rights Equity Shares applied for;
- Total amount paid at the rate of ₹ 22.50 per Rights Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
- In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR / NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
- Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
- All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities" on page of this Letter of Offer and shall include the following:

I/We hereby make representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities" on page 206 of the Letter of Offer.

I/We acknowledge that the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein.

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com).

Our Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

**PLEASE NOTE THAT, IF THE SHAREHOLDER MAKES AN APPLICATION USING THE APPLICATION FORM AS WELL AS PLAIN PAPER, BOTH THE APPLICATION SHALL BE LIABLE TO BE REJECTED AT THE OPTION OF THE ISSUER.**

#### CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:

As your name appears as a beneficial owner in respect of the issued and paid-up Equity Shares held in dematerialised form or appears in the register of members of our Company as an Eligible Equity Shareholder in respect of our Equity Shares held in physical form, as on the Record Date, you may be entitled to subscribe to the number of Rights Equity Shares as set out in the Rights Entitlement Letter.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com)) by entering their DP ID and Client ID or folio number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., [www.indowind.co.in](http://www.indowind.co.in)).

In this regard, our Company has made necessary arrangements with NSDL and CDSL for crediting of the Rights Entitlements to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders in a dematerialized form. A separate ISIN for the Rights Entitlements has also been generated which is INE227G20026. The said ISIN shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date. The said ISIN shall be suspended for transfer by the Depositories post the Issue Closing Date.

Additionally, our Company will submit the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense escrow account to the Stock Exchanges after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholders can be accessed by such respective Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereat.

**Rights Entitlements shall be credited to the respective demat accounts of Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date only in dematerialised form. Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before Issue Closing Date, such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an Application to apply for Rights Equity Shares offered under Issue for subscribing to the Rights Equity Shares offered under Issue.**

If Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date, have not provided the details of their demat accounts to our Company or to the Registrar, they are required to provide their demat account details to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their respective demat accounts, at least one day before the Issue Closing Date. Such Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form can update the details of their respective demat accounts on the website of the Registrar (i.e., [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com)). Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after the Rights Entitlements is credited to their respective demat accounts.

**In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only.**

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "Indowind Energy Limited – Unclaimed Shares Suspense Account") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI ICDR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date; where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details)/records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., by Thursday, August 01, 2024, to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date i.e., by Friday, August 02, 2024, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in the Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard.

Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar is active to facilitate the aforementioned transfer.

#### Procedure for Renunciation of Rights Entitlements

- Renouncees**  
All rights and obligations of the Eligible Equity Shareholders in relation to Applications and refunds pertaining to the Issue shall apply to the Renouncee(s) as well.
- Renunciation of Rights Entitlements**

The Issue includes a right exercisable by Eligible Equity Shareholders to renounce the Rights Entitlements credited to their respective demat account either in full or in part.

The renunciation from non-resident Eligible Equity Shareholder(s) to resident Indian(s) and vice versa shall be subject to provisions of FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time. However, the facility of renunciation shall not be available to or operate in favour of an Eligible Equity Shareholders being an erstwhile OCB unless the same is in compliance with the FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time.

The renunciation of Rights Entitlements credited in your demat account can be made either by sale of such Rights Entitlements, using the secondary market platform of the Stock Exchanges or through an off market transfer.

#### Procedure for Renunciation of Rights Entitlements

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off market transfer (the "Off Market Renunciation"), during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the resident Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date shall be required to provide their demat account details to our Company or the Registrar to the Issue for credit of REs not later than two Working Days prior to Issue Closing Date, such that credit of REs in their demat account takes place at least one day before Issue Closing Date, thereby enabling them to renounce their Rights Entitlements through Off Market Renunciation.

Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

#### Payment Schedule of Rights Equity Shares

₹22.50 per Rights Equity Share (including premium of ₹12.50 per Rights Equity Share) shall be payable on Application.

The Lead Manager and our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors.

#### On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company. In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR

Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN: INE227G20026 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Friday, July 26, 2024 to Wednesday, July 31, 2024 (both days inclusive). The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN: INE227G20026 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of the Stock Exchanges under automatic order matching mechanism and on T+1 rolling settlement basis, where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

#### Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Rights Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN: INE227G20026, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

The renunciation from non-resident Eligible Equity Shareholder(s) to resident Indian(s) and vice versa shall be subject to provisions of FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time. However, the facility of renunciation shall not be available to or operate in favour of an Eligible Equity Shareholders being an erstwhile OCB unless the same is in compliance with the FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time.

#### MAKING AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM:

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in the Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in the Issue:

- The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date;
- The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;
- The remaining procedure for Application shall be same as set out in "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" on page 183 of the Letter of Offer.

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, Resident Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on the Record Date will not be allowed to renounce their Rights Entitlements in the Issue. However, such Eligible Equity Shareholders, where the dematerialized Rights Entitlements are transferred from the suspense escrow demat account to the respective demat accounts within prescribed timelines, can apply for Additional Rights Equity Shares while submitting the Application through ASBA process.

**PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.**

**ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM:** Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. For details, please refer to "Allotment advices or refund/unblocking of ASBA accounts" beginning on page 244 of the letter of offer.

**DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIAL:** In accordance with the SEBI ICDR Regulations, our Company will send through email or registered post or speed post, the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer, Rights Entitlement Letter, the Application Form and other applicable issue material to the email addresses or registered address of all the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company. The Letter of Offer will be provided, only through email, by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who makes a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application form has been completed in electronic form through email Monday, July 22, 2024 by Registrar to the Issue and by speed Post on Monday, July 22, 2024 by the company. The shareholders may obtain duplicate copies of the application form in case they do not receive the application form within a reasonable time after opening of the rights issue from the office of the Registrar. Further, the Letter of Offer will be sent / dispatched, by the Registrar to the Issue on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Further, the Letter of Offer will be provided by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who make a request in this regard. Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of:

- our Company at [www.indowind.co.in](http://www.indowind.co.in);
- the Registrar at [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com);
- the Lead Manager at: and
- the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

#### Last date for Application

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Monday, August 05, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our

Continued to next page...



